Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 11
अंक : 44
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

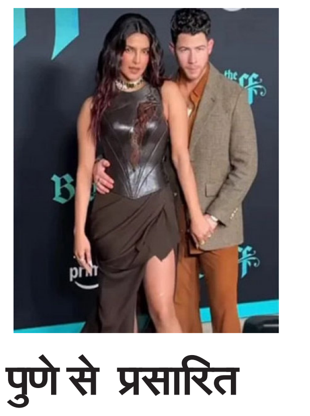

3 छत्रपति शिवराय के मार्ग पर चलना ही विकास...
4 स्वयं सहायता समूह से सशक्तिकरण तकः...
7 अजेय रहते हुए सुपर-8 में पहुंचा जिम्बाब्वे, ...

संक्षिप्त न्यूज

राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू की टिप्पणी से भड़के सचिन पायलट, बोले- बयान वापस लेकर माफी मांगें

मुंबई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पर राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। रिजिजू ने राहुल गांधी को देश की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति बताया था। इस पर पायलट ने कहा कि यह टिप्पणी अपमानजनक और अनुचित है। उन्होंने मुंबई में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यह बात कही। पायलट ने रिजिजू से अपने बयान को वापस लेने और इसके लिए माफी मांगने की मांग की है।
वहीं, राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी पर सचिन पायलट ने कहा कि जब आम पत्रकार सरकार की आलोचना करते हैं तो उन पर एफआईआर हो जाती है और जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब लोकसभा में विपक्ष के नेता को धमकी दी जाती है तो चुप्पी साध ली जाती है। यह सरकार की नीयत को दिखाता है।

सचिन पायलट ने कहा, 'विपक्ष का नेता एक संवैधानिक पद है। उन्हें सुरक्षा के लिए खतरा बताना बहुत ही गलत और अपमानजनक है। खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, फिर भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।' उन्होंने आगे कहा कि रिजिजू को अपना बयान वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। पायलट ने यह भी कहा कि सरकार से सवाल पूछना और जवाबदेही तय करना विपक्ष के नेता का काम है।

इंडिया गठबंधन में नेतृत्व बदलने की मांग पर पायलट ने कहा कि यह गठबंधन का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने बहुत अच्छा काम किया था। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। हम सब मिलकर मजबूती से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।

Global AI पर PM Modi का 3-सूत्रीय 'मास्टरप्लान'

बोले- Data संप्रभुता का हो पूरा सम्मान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया और चेतावनी दी कि 'मानवीय मूल्यों और मार्गदर्शन' के बिना यह तकनीक आत्मघाती साबित हो सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए स्पष्ट मानवीय मूल्यों और दिशा-निर्देशों की नींव आवश्यक है, और कहा कि सार्थक वैश्विक प्रभाव प्राप्त करने के लिए इस तकनीक को मानवीय विश्वास के साथ जोड़ा जाना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के नेताओं के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक जिम्मेदार और मानव-केंद्रित वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्कृष्टता और एआई के नैतिक उपयोग के लिए मेरे तीन सुझाव हैं। पहला, डेटा संप्रभुता का सम्मान करते हुए एआई प्रशिक्षण के लिए एक डेटा ढांचा विकसित किया जाना चाहिए। एआई में कहावत है, 'गलत इनपुट से गलत आउटपुट'। यदि डेटा सुरक्षित, संतुलित और विश्वसनीय नहीं है, तो आउटपुट भरोसेमंद नहीं

होगा। इसलिए, एक वैश्विक विश्वसनीय डेटा ढांचा आवश्यक है। एआई विकास के तकनीकी और कॉर्पोरेट पक्ष की ओर बढ़ते हुए, पीएम मोदी ने 'ब्लैक बॉक्स' एल्गोरिदम संस्कृति के युग को समाप्त करने का आह्वान किया, जहां एआई निर्णय लेने की प्रक्रिया अपारदर्शी और छिपी हुई होती है। उन्होंने पूर्ण पारदर्शिता की ओर बदलाव की वकालत की। उन्होंने कहा कि हमें ब्लैक बॉक्स के बजाय ग्लास बॉक्स दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जहां सुरक्षा नियमों को देखा और सत्यापित किया जा सके। जवाबदेही स्पष्ट होगी और व्यापार में नैतिक व्यवहार को भी बढ़ावा मिलेगा।
एआई सुरक्षा अनुसंधान में एक प्रसिद्ध विचार प्रयोग का हवाला देते हुए, प्रधानमंत्री ने पेपरक्लिप समस्या के बारे में चेतावनी दी - एक ऐसा परिदृश्य जहां पेपरक्लिप बनाने जैसे संकीर्ण लक्ष्य वाली एआई नैतिक दिशा-निर्देशों के अभाव में सभी उपलब्ध संसाधनों का उपभोग कर लेती है। उन्होंने आगाह किया, यदि किसी मशीन को केवल पेपरक्लिप बनाने का लक्ष्य दिया जाए, तो वह ऐसा करना जारी रखेगी, भले ही इसके लिए उसे दुनिया के सभी संसाधनों का उपभोग करना पड़े। ऐसी अनपेक्षित आपदाओं को रोकने के लिए, प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि एआई को अपने मूल प्रोग्रामिंग में स्पष्ट मानवीय मूल्यों और मार्गदर्शन को एकीकृत करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई उत्कृष्टता शून्य में मौजूद नहीं हो सकती। तकनीकी प्रगति को मानवीय नैतिकता के साथ जोड़कर, भारत एक ऐसे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में विश्व का नेतृत्व करना चाहता है जो नवोन्मेषी और सुरक्षित दोनों हो।

इमैनुएल मैक्रों बोले- राफेल डील से भारत मजबूत हो रहा, लोग कैसे कर सकते हैं आलोचना

नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गुरुवार को भारत के 114 राफेल जेट खरीदने की योजना का बचाव किया। इमैनुएल मैक्रों ने इस खरीद समझौते की आलोचना पर भी जवाब दिया। मैक्रों ने कहा, 'हम स्वदेशी घटकों को लगातार बढ़ा रहे हैं। यह कंपनी और आपकी सरकार के बीच चल रही बातचीत का हिस्सा है। मुझे नहीं पता, लोग इसकी आलोचना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका देश मजबूत होता है।'

मैक्रों ने 'मेक इन इंडिया' का जिक्र कर क्या कहा?

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा, 'हमारी सिर्फ रणनीतिक साझेदारी नहीं है, बल्कि एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है जो भारत और फ्रांस दोनों के लिए अद्वितीय है। राफेल के मामले में, हम इसका विस्तार करना चाहते हैं। भारत ने कुछ दिन पहले राफेल 114 मिसाइलों की नई खेप लेने और सह-उत्पादन करने की अपनी इच्छा की पुष्टि की है। इस नई खेप में 'मेक इन इंडिया' मुख्य आधार होगा।'
मैक्रों ने आगे कहा, 'इसके अलावा, हम रखरखाव क्षमताओं में सहयोग को बेहतर बनाना चाहते हैं, दृष्टिकोण में विविधता लाना चाहते हैं और इसे आपसी सहमति पर आधारित सहयोग बनाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम पनडुब्बियों के मामले में भी ऐसा ही करेंगे।'

भारत में पैदा होंगी नौकरियां :मैक्रों

इमैनुएल मैक्रों ने अपने में मेक इन इंडिया और इससे पैदा होने वाली नौकरियों के बारे में इशारा किया। उन्होंने कहा, 'इससे हमारे बीच रणनीतिक समन्वय बढ़ता है और यहां अधिक रोजगार सृजित होते हैं। स्पष्ट रूप से, हम अधिकतम संख्या में भारतीय घटकों का उपयोग करने और भारत में अधिकतम संख्या में महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।'

टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती की बढ़ी मुश्किलें, मिला 20 लाख का मानहानि नोटिस

कोलकाता। बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री और पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद मिमी चक्रवर्ती को कार्यक्रम आयोजक तनय शास्त्री ने मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। यह विवाद उस मामले से जुड़ा है, जिसमें शास्त्री पर पहले उत्पीड़न का आरोप लगा था।

तनय शास्त्री ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने मिमी चक्रवर्ती को 20 लाख रुपए का हर्जाना देने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए नोटिस भेजा है। इस पर मिमी चक्रवर्ती की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

इवेंट ऑर्गनाइजर ने किया क्या दावा?

मीडिया से बातचीत में शास्त्री ने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मिमी चक्रवर्ती को 2 लाख 65 हजार रुपए का भुगतान किया गया था। उनका आरोप है कि अभिनेत्री निर्धारित समय पर कार्यक्रम में नहीं पहुंचीं, इसलिए उनसे राशि लौटाने को कहा गया। उन्होंने यह भी कहा कि बिना किसी कारण उनके खिलाफ मामला दर्ज कराकर उनकी छवि खराब की गई और उन्हें न्यायिक हिरासत तक में जाना पड़ा। शास्त्री ने कहा कि अगर अभिनेत्री माफी नहीं मांगतीं या 20 लाख रुपए का भुगतान नहीं करतीं, तो अगले दो-तीन दिनों में अदालत में मानहानि का मामला दायर किया जाएगा।

मिलन 2026 के उद्घाटन में राजनाथ सिंह बोले- भारत स्थापित करना चाहता है समतामूलक समुद्री व्यवस्था

विशाखापत्तनम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानून और नौवहन की स्वतंत्रता पर आधारित एक समतामूलक समुद्री व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना होगा।

पारंपरिक खतरों के साथ उभर रही अन्य चुनौतियां :रक्षा मंत्री

उन्होंने कहा, 'पारंपरिक खतरों के साथ-साथ उभरती चुनौतियां भी मौजूद हैं। समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, अवैध मछली पकड़ना, तस्करी, साइबर जोखिम और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं

में व्यवधान जैसी समस्याएं गंभीर हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, जिससे मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों की मांग भी बढ़ी है।'
राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई भी एक नौसेना इन चुनौतियों से अकेले नहीं निपट सकती, इसलिए सहयोग अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय जल से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए 'युनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी' एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। उन्होंने व्यापक वैश्विक नौसैनिक संरचना की जरूरत पर बल दिया, जो सूचना साझाकरण, समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण सुनिश्चित करे।

भारत की समुद्री नीति 'सागर' से आगे बढ़कर 'महासागर' दृष्टि तक विकसित :राजनाथ सिंह

उन्होंने बताया कि भारत की समुद्री नीति 'सागर' से आगे बढ़कर 'महासागर' दृष्टि तक विकसित हुई है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि 74 देशों की भागीदारी के साथ मिलन 2026 अब तक का सबसे बड़ा और समावेशी संस्करण है, जो भारत पर वैश्विक समुद्री समुदाय के विश्वास को दर्शाता है।

अब पूरे देश में एसआईआर की तैयारी

चुनाव आयोग ने 22 राज्यों-UTs को जल्द तैयारी पूरी करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को कहा कि 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होगा। आयोग ने राज्यों से इससे संबंधित तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) इसके दायरे में आ जाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया कि इस अभ्यास के पूरा होने के बाद देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इसके दायरे में लाया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए पत्र में जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं।
चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि नौ

राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में यह जारी है। वहीं असम में एसआईआर के बजाय 'स्पेशल रिवीजन' प्रक्रिया 10 फरवरी को पूरी कर ली गई। निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाता सूची के अखिल भारतीय एसआईआर का आदेश पिछले साल जून में दिया गया था।

एसआईआर में क्या-क्या किया जाएगा?

उन्होंने बताया कि हर घर पर बीएलओ तीन बार जाएंगे और मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे। इस दौरान बीएलओ की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी योग्य मतदाता इस अभियान न छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता नहीं जुड़े। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया होनी है, वहां आज रात 12 बजे से मतदाता सूची फ्रीज हो जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान दूसरे राज्यों में प्रवास करने वाले मतदाता ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त

क्या है एसआईआर का उद्देश्य?

विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची में सुधार करना और इसमें नए मतदाताओं का समावेश करना है। इसमें नामों की जांच, पुराने मतदाताओं की पुष्टि, और आवश्यक संशोधन शामिल होंगे। आयोग ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। एसआईआर के तहत मतदाता सूची में त्रुटियों को दूर कर नए मतदाताओं को शामिल किया जाएगा, जिससे चुनावों में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

2026 में इन राज्यों में होने है विधानसभा चुनाव

बता दें कि देश के पांच राज्यों में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें असम, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। हालांकि, जिन राज्यों में इस समय स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं या होने वाले हैं, वहां फिलहाल यह प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि स्थानीय स्तर का प्रशासन चुनावी कामकाज में व्यस्त रहेगा।

प्रियंका गांधी ने जारी की भाजपा सरकार के खिलाफ जनता की चार्जशीट, लगाए ये 20 गंभीर आरोप

गुवाहाटी। आगामी असम विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के असम दौरे के दौरान 'जनता की चार्जशीट' जारी की। इस चार्जशीट के जरिए कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है। इसमें राज्य सरकार पर बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, किसानों की अनदेखी, शिक्षा व्यवस्था में गिरावट और सामाजिक भाईचारा बिगाड़ने जैसे कुल 20 आरोप लगाए गए हैं।
प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि यह चार्जशीट जनता से मिली राय और जमीनी सर्वे के आधार पर तैयार की गई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के वादे पूरे नहीं किए। साथ ही, सरकार महंगाई पर लगाम लगाने और किसानों को फसलों का सही दाम दिलाने में भी नाकाम रही है।
अपने दो दिवसीय दौरे पर पहुंचीं प्रियंका गांधी ने गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ कार्यक्रम

की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस असम में शांति, एकता और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाएगी। इसके बाद उन्होंने पार्टी दफ्तर राजीव भवन में स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता की। इस बैठक में उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, स्थानीय नेताओं की राय को प्राथमिकता देने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर चर्चा हुई।
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज को चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाएगी। उन्होंने महिला और युवा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सरकार की नाकामियों को घर-घर तक पहुंचाएं। दूसरी ओर, भाजपा ने प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस नेता इमरान मसूद की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर समाज को बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। हालांकि, कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। जानकारों का मानना है कि इस चार्जशीट के बाद असम का चुनावी मुकाबला सीधे मुद्दों की लड़ाई बनाने की कोशिश की है।

टीएमसी में शामिल हुए भाजपा विधायक बिष्णु प्रसाद शर्मा, 2024 में निर्दलीय लड़ा था लोकसभा चुनाव

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला शुरु हो गया है। भाजपा से अलग हुए विधायक बिष्णु प्रसाद शर्मा ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बिष्णु कुर्सियांग से पहली बार विधायक बने हैं। वह कोलकाता में पार्टी के हेडक्वार्टर में टीएमसी में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु और उद्योग मंत्री शशि पांजा ने पार्टी में उनका स्वागत किया। बिष्णु प्रसाद शर्मा ने कहा कि मुझे मेरे गोरखा भाइयों और बहनों ने चुना था, लेकिन मैं उनके लिए काम नहीं कर पाया। भाजपा ने वादे किए लेकिन कुछ नहीं किया। ज़मीन पर कोई असली काम नहीं हुआ। शर्मा ने बार-बार अलग गोरखालैंड राज्य की मांग का समर्थन किया था, उनका तर्क था कि हिल्स को खास प्रशासन और विकास की जरूरत है। उन्होंने कई बार अलग नॉर्थ बंगाल राज्य की मांग भी उठाई थी।
शर्मा ने पहले भी कई भाजपा की बुराई की थी, और गोरखालैंड की मांग पर कोई एक्शन न लेने को लेकर विधानसभा के

बाहर प्रदर्शन किया था। उन्होंने 2024 का लोकसभा में दार्जिलिंग सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, और खुद को धरती का बेटा बताया था। हालांकि, यह कोशिश कामयाब नहीं हुई, और भाजपा के राजू बिस्टा ने सीट जीत ली।

पीएम मोदी के 'मानव' विजन पर कांग्रेस का तंज, जयराम रमेश बोले- इसका कोई इलाज नहीं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए 'मानव' विजन की बात कही। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'इस (ए) क्रोनिम (आई) इंफेक्शन का कोई इलाज नहीं है।' उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा 'प्रधानमंत्री ने एआई के लिए अपना मानव विजन पेश किया है। इस (ए)क्रोनिम (आई)इंफेक्शन का कोई इलाज नहीं है।'

पीएम मोदी ने एआई को साझा करने की बात कही

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मानव-केंद्रित दृष्टिकोण और संप्रभुता और समावेशिता पर जोर देने के साथ तेजी से उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए मानव दृष्टिकोण का अनावरण किया। यहां एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वास्तव में दुनिया की भलाई के लिए तभी काम आएगी, जब इसे साझा किया जाएगा और इसके कोड खुले होंगे।

उन्होंने जोर देकर कहा कि देश एआई से डरता नहीं है बल्कि इसमें एक भविष्य और भविष्य की रूपरेखा देखता है।

क्या है मानव

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी का कल्याण और खुशी एआई के लिए हमारा मानदंड है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मनुष्य डेटा पॉइंट या कच्चा माल न बन जाएं। मोदी ने कहा, 'मैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए मानव दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हूं, जहां (एम) नैतिक और नीतिपरक प्रणालियों के लिए, (ए) जवाबदेह शासन के लिए, (एन) राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए, (ए) सुलभ और समावेशी के लिए, और (वी) वैध और कानूनी के लिए है।'

कई देशों के दिग्गज हुए शमिल

इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन सहित वैश्विक नेता और दुनिया भर की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के सीईओ उपस्थित थे।

Bombay High Court का ऐतिहासिक फैसला, Rape Survivor का बच्चा अपनाएगा मां का सरनेम और जाति

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भारत के विकसित होते संवैधानिक मूल्यों और लैंगिक न्याय को लेकर चल रही चर्चाओं से मेल खाते एक ऐतिहासिक फैसले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि एक बच्चा अपनी बलात्कार पीड़िता एकल मां का नाम, उपनाम और जाति धारण कर सकता है। न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और हितेन एस वेनेगावकर की खंडपीठ ने महाराष्ट्र के बीड जिले की 12 वर्षीय लड़की और उसकी मां को राहत प्रदान करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी बच्चे की नागरिक पहचान के एकमात्र स्रोत के रूप में एकल मां को कानूनी मान्यता देना समाज को कमजोर करने के बजाय मजबूत करता है। पीठ ने टिप्पणी की जहां तथ्य इसकी पुष्टि करते हैं, वहां एक अकेली मां को बच्चे की नागरिक पहचान, नाम जिसमें वंश का विवरण शामिल है, और जाति के पूर्ण स्रोत के रूप में मान्यता देना समाज को कमजोर

नहीं करता है, बल्कि इसके विपरीत, इसे सभ्य बनाता है।

न्यायाधीशों ने आगे कहा कि यह फैसला कानूनी चिंतन में एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है, जो पितृसत्तात्मक आदेशों से हटकर संवैधानिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत गरिमा पर आधारित मूल्यों की ओर अग्रसर है। यह स्वीकार करते हुए कि एक माँ हर मायने में एकमात्र और पूर्ण अभिभावक हो सकती है, यह कानून पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने से कहीं अधिक करता है; यह इस मूलभूत वादे को सुदृढ़ करता है कि किसी भी व्यक्ति–विशेषकर बच्चे–को अपने जन्म की परिस्थितियों या अपने माता-पिता के कुकर्मों का बोझ नहीं उठाना चाहिए।

यह मामला स्कूल के आधिकारिक रिकॉर्ड में लड़की का नाम, उपनाम और जाति बदलने की अनुमति मांगने वाली याचिका से उत्पन्न हुआ। मां और बेटी ने जाति का नाम 'मराठा' से बदलकर 'अनुसूचित जाति - महार' करने की मांग की, जो मां की पहचान को दर्शाता है। लड़की का जन्म उसके जैविक पिता द्वारा उसकी मां पर किए गए यौन हमले के बाद हुआ था। आपराधिक जांच के दौरान किए गए डीएनए परीक्षण ने उसके पिता होने की पुष्टि की, जिसके परिणामस्वरूप जन्म प्रमाण पत्र और बाद में स्कूल और संबंधित रिकॉर्ड में उसका नाम पिता के रूप में दर्ज किया गया। 14 दिसंबर, 2022 को मां और आरोपी पिता के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत मां को बच्ची की स्थायी अभिरक्षा प्रदान की गई।

पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कारवाई की आवश्यकता - मंत्री पंकजा मुंडे

दिव्यांश

मुंबई। पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस एवं व्यापक स्तर पर कार्रवाई का आह्वान करते हुए पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि अतीत में विकास और आधारभूत सुविधाओं पर जोर देते समय पर्यावरण की उपेक्षा हुई। इसके परिणाम आज पूरे विश्व को भुगतने पड़ रहे हैं। पर्यावरण का प्रश्न किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका स्वरूप वैश्विक है। इसलिए इसके समाधान हेतु वैश्विक दृष्टिकोण आवश्यक है।

मिट्टी, पानी और हवा पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं। औद्योगिकीकरण और बढ़ती आधारभूत सुविधाओं के कारण इन तीनों पर दबाव उत्पन्न हुआ है। आर्थिक रूप से पिछड़े देशों ने विकास के लिए पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाले उद्योगों को अनुमति दी और अब उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, ऐसा मंत्री मुंडे ने उल्लेख किया।

पर्यावरण संबंधी सम्मेलनों में होने वाली चर्चाएँ केवल बौद्धिक स्तर तक सीमित न रहकर उनका व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन होना चाहिए, ऐसी आशा व्यक्त करते हुए, मुंबई क्लाइमेट वीक के माध्यम से विभिन्न देशों के विशेषज्ञों के साथ विचार-विनिमय का अवसर मिलने पर मंत्री मुंडे ने संतोष व्यक्त किया।

जलवायु लचीलापन के लिए सार्वत्रिक प्रयास आवश्यक - महापौर रितु तावडे

शहर का विकास, विस्तार और जलवायु उत्तरदायित्व–इन तीनों को अलग-अलग न रखते हुए समानांतर एवं समन्वित रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा मुंबई की महापौर रितु तावडे ने कहा। जलवायु लचीलापन केवल शासन तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक संस्थानों, निजी उद्योगों, वित्तीय भागीदारों, अनुसंधान संस्थानों और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से ही संभव होगा। इसके लिए सुदृढ़ सार्वजनिक-निजी भागीदारी, नवोन्मेषी वित्तपोषण, तकनीकी सहयोग और नागरिकों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक हैं, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया।

'हिंद-दी-चादर' अंतर्गत 6 स्थानों की गहन स्वच्छता अभियानों में स्वच्छताकर्मियों सहित 527 जनों की सहभागिता

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

सुपर स्वच्छ लीग में देश के अग्रणी शहर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त नवी मुंबई महानगरपालिका द्वारा हिंद-दी-चादर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में गहन स्वच्छता अभियान संचालित किए जा रहे हैं तथा उन्हें नागरिकों का भी अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हो रहा है। उसी संदर्भ में कोपरखैरणे महानगरपालिका विद्यालय क्रमांक 31 में, वाशी सेक्टर 10 क्षेत्र में, तुर्भे विभाग के सानपाड़ा गुरुद्वारा सेक्टर 9 क्षेत्र में, सायन पनवेल महामार्ग स्थित बेलापुर भाग में, ऐरोली सेक्टर -

1 गुरुद्वारा क्षेत्र में तथा दिघा विभाग के विष्णुनगर एवं आसपास के पर्वतीय क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान अत्यंत प्रभावी रूप से संचालित किए गए।

वित्त वर्ष 2025-26 में मध्य रेल ने 1373 मिलियन से अधिक यात्रियों को परिवहन प्रदान किया

मुंबई उपनगरीय ट्रेन सेवाओं ने जनवरी 2026 में 127 मिलियन से अधिक यात्रियों को परिवहन प्रदान किया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

वित्त वर्ष 2025-26 (जनवरी 2026 तक) के दौरान मध्य रेल ने यात्री परिवहन में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है, जिसमें उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों खंडों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है।

मध्य रेल ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 1373.39 मिलियन यात्रियों को परिवहन प्रदान किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में परिवहन किए गए 1348.33 मिलियन यात्रियों की तुलना में 1.86इ की वृद्धि दर्शाता है।

इसमें शामिल हैं:

वित्त वर्ष 2025-26 में उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1201.93 मिलियन है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 1187.92 मिलियन थी।

वित्त वर्ष 2025-26 में मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर और अन्य गैर-उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 171.46 मिलियन थी, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 160.41मिलियन थी।

जनवरी 2026 के दौरान, मध्य रेल ने 146.29 मिलियन यात्रियों (जिनमें 129.08 मिलियन उपनगरीय और 17.2 करोड़ गैर-उपनगरीय यात्री शामिल हैं) का परिवहन किया। 129.08 मिलियन उपनगरीय यात्रियों में मुंबई उपनगरीय लाइन पर 127.12 मिलियन और पुणे उपनगरीय लाइन पर 1.96 मिलियन यात्री शामिल हैं। नेरुल/बेलापुर-उरण खंड पर अतिरिक्त सेवाओं की शुरुआत और इस मार्ग पर दो नए स्टेशनों, तरघर और गवान स्टेशनों के चालू होने से उपनगरीय ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

हार्बर लाइन पर एसी सेवाओं की शुरुआत को जबरदस्त प्रतिसाद मिला है, जिसके चलते महज 16 दिनों में 6 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की है। यह यात्रियों की बेहतर सुविधा और दक्षता के प्रति प्रबल रुचि को दर्शाता है।

वर्तमान में, मध्य रेल मुंबई महानगर क्षेत्र में बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने के लिए 94 एसी लोकल सेवाओं सहित 1820 उपनगरीय सेवाएं संचालित करता है।

मध्य रेल अपने सभी यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक, किफायती, विश्वसनीय और कुशल परिवहन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और यात्रियों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी सेवाओं को सुदृढ़ करना जारी रखता है।

पश्चिम रेलवे ने मिशन जीरो स्क्रैप के तहत स्क्रैप बिक्री में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्क्रैप निपटान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि मिशन जीरो स्क्रैप के अंतर्गत पश्चिम रेलवे की अपने सभी प्रतिष्ठानों एवं इकाइयों को स्क्रैप-मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे ने 17 फरवरी, 2026 तक कुल 506.63 करोड़ रुपये की स्क्रैप बिक्री दर्ज की है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा 470 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम रेलवे ने यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) की तुलना में 5 सप्ताह पहले हासिल कर ली है। पिछले वर्ष यह उपलब्धि 21 मार्च, 2025 को प्राप्त हुई थी।

यह उपलब्धि पश्चिम रेलवे के कुशल परिसंपत्ति प्रबंधन, बेहतर हाउसकीपिंग तथा स्क्रैप सामग्री की समय पर पहचान एवं निपटान के माध्यम से संसाधनों के इष्टतम उपयोग के सतत प्रयासों को दर्शाती है।

मनपा द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनायी गयी

मंत्र भारत। भाईदंर

19 फरवरी को मीरा भायंदर शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती बड़े जोश के साथ मनाई गई।सुबह 08.15 बजे, घोड़बंदर काशीमीरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के घुड़सवारी स्मारक महापौर डिंपल मेहता, डिप्टी मेयर ध्रुवकिशोर पाटिल कमिश्नर राधाबिनोद शर्मा ने फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद, सुबह 09.00 बजे, भायंदर वेस्ट गेट पर महापुरुष डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की मूर्ति पर फूल चढ़ाए गए। उसके बाद, मनपा मुख्यालय के सामने आंगन में छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेड ऑफिस की दूसरी मंजिल पर महापौर डिंपल मेहता डिप्टी मेयर ध्रुवकिशोर पाटिल, मनपा कमिश्नर राधाबिनोद शर्मा के हाथों से छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई।इस अवसर पर शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर महापौर डिंपल मेहता ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकारों और नागरिकों को शुभकामनाएं दीं।

सघन टिकट जांच अभियान में बिना टिकट यात्रिओं पर सख्त कार्रवाही

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा वैध यात्रियों को सुगम एवं सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करने तथा बिना टिकट/अनियमित यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निरंतर गहन टिकट जांच अभियान संचालित किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नरेन्द्र कुमार के निर्देशन में आयोजित दिनांक 17.02.2026 को चलाए गए टिकट जांच अभियान में कुल 931 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 397 मामले बिना टिकट यात्रा के थे। जिसके फलस्वरूप यात्रियों से जुर्माने के रूप में कुल 5,82,750 की दंड राशि वसूल की गई। यह उपलब्धि नियमित टिकट जांच व्यवस्था, क्षेत्रीय पर्यवेक्षण में वृद्धि तथा वाणिज्य एवं टिकट जांच स्टाफ के समन्वित प्रयासों का परिणाम है।

उल्लेखनीय है कि यह सफलता बिना किसी विशेष फोर्ट्रेस, मजिस्ट्रेट अथवा अधिकारी-स्तरीय विशेष अभियान के, नियमित प्रवर्तन कार्यवाही के माध्यम से प्राप्त की गई है।

मरम्मत कार्य के कारण समपर संख्या 253 से रात्रि में आवागमन अस्थाई रूप से बंद

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

रतलाम। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के इंदौर-राजेन्द्र नगर रेल खंड में स्थित समपार फाटक क्रमांक 253 पर रेलवे ट्रैक का मरम्मत कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए रात्रि समय में इस समपार फाटक से सड़क यातायात बंद रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार ने बताया कि संरक्षा को ध्यान में रखकर एक नियमित अंतराल पर ट्रैक मरम्मत कार्य किया जाता है। इसी क्रम में समपार फाटक क्रमांक 253 पर भी मरम्मत कार्य किया जाएगा। मरम्मत कार्य किये जाने के कारण 20 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक रात्रि 20.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे ाक समपार क्रमांक 253 से सड़क यातायात बंद रहेगा। सड़क उपयोगकर्ता इस दौरान असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में केसरबाग रोड ओवर ब्रिज का उपयोग कर सकते हैं।

रेलवे द्वारा होली के लिए 30 अतिरिक्त विशेष ट्रेन सेवाएं चलाई जाएंगी

रेलवे निम्नलिखित अनुसार होली के लिए 30 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाएगा:

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

एलटीटी मुंबई और सुल्तानपुर / वाराणसी के बीच 8 ट्रेन सेवाएं और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए एलटीटी मुंबई और रक्सौल / सहरसा / धनबाद के बीच 22 ट्रेन सेवाओं का विस्तार।

विवरण इस प्रकार है:

एलटीटी मुंबई और सुल्तानपुर / वाराणसी के बीच 8 होली विशेष ट्रेन सेवाएं चलाएगाङ

लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई - सुल्तानपुर - लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई एसी विशेष(4 सेवाएं)

04211 होली विशेष ट्रेन दिनांक 27.02.2026 और दिनांक 03.03.2026 को दोपहर 14:35 बजे एलटीटी मुंबई से प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 23:00 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी (2 सेवा)।

होली विशेष ट्रेन संख्या 04212 सुल्तानपुर से दिनांक 26.02.2026 और दिनांक 02.03.2026 को सुबह 04:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 12:20 बजे एलटीटी मुंबई पहुंचेगी। (2 सेवाएं)।

ठहरावः- ठाणे, कल्याण, नाशिक रोड, चालीसगांव, पचोरा, भुसावल, खंडवा, इटारसी जंक्शन, रानी कम्पलपति, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, उरई, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ।

लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई - वाराणसी - लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई एसी विशेष (4 सेवाएं)

04225 होली विशेष ट्रेन दिनांक 26.02.2026 और दिनांक 02.03.2026 को 14:35 बजे एटीटी मुंबई से प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन 02:05 बजे वाराणसी पहुंचेगी (2 सेवाएं)।

04226 होली विशेष ट्रेन दिनांक 25.02.2026 और 01.03.2026 को 01:35 बजे वाराणसी से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 12:20 बजे एटीटी मुंबई पहुंचेगी (2 सेवाएं)।

ठहरावः-ठाणे, कल्याण, नाशिक रोड, चालीसगांव, पचोरा, भुसावल, खंडवा, इटारसी जंक्शन, रानी कम्पलपति, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, उरई, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ सुल्तानपुर और जौनपुर सिटी

04211 / 04212 और 04225 / 04226 के लिए संरचनाः 16 एसी 3-टियर इकोनॉमी और 2 जेनरेटर वैन (बी)। एलटीटी-रक्सौल, एलटीटी-सहरसा और एलटीटी-धनबाद के लिए 22 होली विशेष ट्रेन सेवाओं का विस्तार

एलटीटी मुंबई-रक्सौल-एलटीटी मुंबई का होली विशेष के रूप में विस्तार (8 सेवाएं)

05558 एलटीटी-रक्सौल विशेष, जो प्रत्येक गुरुवार को चलती है और पहले दिनांक 27.11.2025 तक चलने के लिए अधिसूचित थी, अब होली विशेष के

रूप में दिनांक 12.03.2026 से दिनांक 02.04.2026 तक विस्तारित की गई है। (4 सेवाएं)

05557 रक्सौल-एलटीटी विशेष, जो प्रत्येक मंगलवार को चलती है और पहले दिनांक 25.11.2025 तक चलने के लिए अधिसूचित थी, अब होली विशेष के रूप में दिनांक 10.03.2026 से दिनांक 31.03.2026 तक विस्तारित की गई है। (4 सेवाएं)

संरचनाः 1 फर्स्ट एसी सह 2 एसी टियर, 2 एसी 2-टियर, 6 एसी 3-टियर, 7 शयनयान श्रेणी, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 1 द्वितीय श्रेणी सीटिंग सह गार्ड की ब्रेक वैन और 1 जनरेटर कार।

एलटीटी मुंबई-सहरसा-एलटीटी मुंबई का होली विशेष के रूप में विस्तार (8 सेवाएं)

05586 एलटीटी-सहरसा विशेष, जो प्रत्येक रविवार को चलती है और पहले दिनांक 30.11.2025 तक चलने के लिए अधिसूचित थी, अब होली विशेष के रूप में दिनांक 08.03.2026 से दिनांक 29.03.2026 तक बढ़ा दी गई है। (4 सेवाएं)

05585 सहरसा-एलटीटी विशेष, जो प्रत्येक शुक्रवार को चलती है और पहले दिनांक 28.11.2025 तक चलने के लिए अधिसूचित थी, अब होली विशेष के रूप में दिनांक 06.03.2026 से दिनांक 27.03.2026 तक बढ़ा दी गई है। (4 सेवाएं)

संरचनाः 2 एसी 2-टियर, 6 एसी 3-टियर, 2 एसी 3-टियर इकोनॉमी, 6 शयनयान श्रेणी, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 1 सेकंड सीटिंग सह गार्ड्स ब्रेक वैन और 1 जेनरेटर कार।

एलटीटी मुंबई-धनबाद - एलटीटी मुंबई का होली विशेष के रूप में विस्तार (6 सेवाएं)

03380 एलटीटी-धनबाद विशेष, जो प्रत्येक गुरुवार को चलती है और पहले दिनांक 15.01.2026 तक चलने के लिए अधिसूचित थी, अब होली विशेष के रूप में दिनांक 12.03.2026 से दिनांक 26.03.2026 तक बढ़ा दी गई है। (3 सेवाएं) 03379 धनबाद-एलटीटी विशेष, जो प्रत्येक मंगलवार को चलती है और पहले दिनांक 13.01.2026 तक चलने के लिए अधिसूचित थी, अब होली विशेष के रूप में दिनांक 10.03.2026 से दिनांक 24.03.2026 तक बढ़ा दी गई है। (3 सेवाएं)

संरचनाः 2 एसी 2-टियर, 2 एसी 3-टियर, 6 एसी 3-टियर इकोनॉमी, 6 शयनयान श्रेणी , 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 1 सेकंड सीटिंग सह गार्ड्स ब्रेक वैन और 1 जेनरेटर कार।

ट्रेन संख्या 05558/05557, 05586/05585 और 03380/03379 के समय और ठहराव में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आरक्षणः होली विशेष ट्रेन संख्या 05558, 05586 और 03380 की विस्तारित यात्राओं के लिए बुकिंग दिनांक 20.02.2026 से शुरू होगी औरङएसी होली विशेष ट्रेन संख्या 04211 और 04225 के लिए बुकिंग दिनांक 22.02.2026 से शुरू होगी। सभी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और वेबसाइट http://www.irctc.co.in पर बुकिंग उपलब्ध है। अनारक्षित कोचों के लिए सामान्य शुल्क पर बुकिंग यूटीएस प्रणाली के माध्यम से की जा सकती है। यात्री टिकट बुकिंग के लिए रेलवन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।

इन विशेष ट्रेनों के ठहराव के विस्तृत समय के लिए, कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएं या एनटीईएस ऐप डाउनलोड करें।

पश्चिम रेलवे

ई-नीलामी बिक्री कार्यक्रम में संशोधन

सामग्री प्रबंधन विभाग

ई-नीलामी बिक्री सूचना क्रमांक SIII/Auction Programme-I / MARCH-2026 दिनांक 05.02.2026 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि PARDI डिपो में माह MARCH-2026 में आयोजित की जाने वाली ई-नीलामी बिक्री, जो 17.03.2026 एवं 29.03.2026 को निर्धारित थी, उसे पुनर्निर्धारित किया गया है। अब उक्त ई-नीलामी बिक्री क्रमशः 11.03.2026 एवं 18.03.2026 को आयोजित की जाएगी। अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

(SIII/Auction Programme-II / MARCH-2026, दिनांक 16.02.2026) 1139

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

किले शिवनेरी पर छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मोत्सव मनाया गया

छत्रपति शिवराय के मार्ग पर चलना ही विकास का सच्चा मार्ग- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

छत्रपति शिवराय द्वारा प्रदर्शित मार्ग ही सर्वांगीण विकास का मार्ग है। उनके कार्य का आदर्श विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु 2030 में छत्रपति शिवाजी महाराज की 400 वी जयंती भव्य तथा वैश्विक स्तर पर मनाई जाएगी, ऐसा प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया।

वे किल्ले शिवनेरी पर आयोजित शिवजन्मोत्सव समारोह में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा जिले की पालकमंत्री सुनेत्रा पवार, सांस्कृतिक कार्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ?ड. आशिष शेलार, विधायक शरद सोनवणे, पूर्व विधायक अतुल बेनके, कोल्हापुर परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिला पुलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, उपवनसंरक्षक आशिष ठाकरे, अभिनेता रितेश देशमुख तथा मराठा सेवा संघ के प्रदेशाध्यक्ष विजय घोगरे सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि छत्रपति

शिवाजी महाराज नहीं होते तो आज भारत का इतिहास और भूगोल भी भिन्न होता। अनेक राजा-रजवाड़े जब मुगल आधिपत्य में कार्य कर रहे थे, तब माता जिजाऊ द्वारा संस्कारित छत्रपति शिवराय ने प्रजा का स्वराज्य स्थापित कर हिंदुस्थान को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने 18 पगड जातियों के मावलों को एकत्र कर स्वराज्य की स्थापना की और यह स्पष्ट किया कि यह उनका व्यक्तिगत राज्य नहीं, बल्कि प्रजा का राज्य है। देव, देश और धर्म के लिए संघर्ष की प्रेरणा देते हुए उन्होंने सामान्य जन को मुगल अत्याचारों से मुक्त कराया। उनके राज्य में समता, सम्मान, न्याय और स्त्री सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। किसान संतुष्ट रहे और अन्याय-अत्याचार न हों, ऐसी शासन व्यवस्था उन्होंने स्थापित की।

राजकारभार में सुधार करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने लगभग 50 प्रकार के कर समाप्त कर सरल कर व्यवस्था स्थापित की। जल और वन संसाधनों का नियोजन किया। भविष्य के संकट को पहचानते हुए समुद्री आक्रमणों को रोकने के लिए जलदुर्गों का निर्माण किया। पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त कर पश्चिमी तट को सुरक्षित किया। उनके शासनकाल में समुद्र मार्ग से आक्रमण करने का साहस किसी ने नहीं किया, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शिवराय के पराक्रम की साक्षी राज्य के दुर्ग हैं। प्रधानमंत्री के प्रयासों से शिवनेरी सहित छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 दुर्गों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया गया है और 27 देशों ने सर्वसम्मति से इसे मान्यता प्रदान की है। सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार ने संबंधित प्रमाणपत्र स्वीकार किया। इस प्रकार शिवराय के दुर्ग अब आधिकारिक रूप से विश्व धरोहर स्थल के रूप में गौरवान्वित हुए हैं। राज्य के सभी दुर्गों को अतिक्रमणमुक्त करने का निर्णय शासन ने लिया है।

मराठा सेवा संघ के निवेदन पर राज्य सरकार सकारात्मक रूप से कार्य करेगी तथा प्रस्तुत सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा, ऐसी ग्वाही देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य एवं विश्वभर के शिवभक्तों को शिवजयंती की शुभकामनाएँ दीं।

पर्यावरण विशेषज्ञों को कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता- राज्यपाल आचार्य देवव्रत

राज्यपाल की उपस्थिति में मुंबई क्लाइमेट वीक का समापन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

कृषि क्षेत्र में रसायनों के बढ़ते उपयोग के कारण खेती के साथ-साथ पर्यावरण को भी भारी क्षति हो रही है। रासायनिक खेती के दुष्परिणाम अत्यंत घातक हैं। इसके परिणामस्वरूप समग्र पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, साथ ही गंभीर रोगों का संकट भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए पर्यावरण विशेषज्ञों को वैश्विक पर्यावरण संरक्षण पर विचार करते समय कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा आह्वान महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया।

वे मुंबई स्थित जिओ वर्ल्ड सेंटर में आयोजित 'मुंबई क्लाइमेट वीक' के समापन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ?ड. आशिष शेलार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे, मुंबई की महापौर रितु तावडे, पर्यावरण विभाग की प्रधान सचिव जयश्री भोज, राज्यपाल के सचिव प्रशांत नारनवरे, सहसचिव एस. राममूर्ति, प्रोजेक्ट मुंबई के शिशिर जोशी, जलज दानी तथा पर्यावरण प्रेमी उपस्थित थे। 'मुंबई क्लाइमेट वीक' की तीन दिवसीय परिषद के माध्यम से जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर विषय पर देश-विदेश के विशेषज्ञों द्वारा मंथन किए जाने के लिए राज्यपाल ने आयोजकों का अभिनंदन किया। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति प्रकृति पूजक है। प्राचीन शिक्षा पद्धति में बच्चों को प्रकृति के सान्निध्य में शिक्षा दी जाती थी। किंतु आधुनिक काल में भोगवादी प्रवृत्तियों के बढ़ने से पर्यावरण का क्षरण हुआ है। कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान जब मनुष्य घरों में रहा, तब नदियाँ स्वच्छ हुईं और आकाश निर्मल दिखाई देने लगा। इससे स्पष्ट होता है कि पर्यावरण क्षरण का प्रमुख कारण मानवीय हस्तक्षेप ही है।

राज्यपाल ने रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग, साथ ही यूरिया, डीएपी और कीटनाशकों के कारण 'नाइट्रस ऑक्साइड' जैसे गैसों के पर्यावरण पर पड़ने वाले घातक प्रभावों को रेखांकित किया। इन रसायनों के अंश भूजल तथा खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। रासायनिक खेती से भूमि अनुपजाऊ हो रही है, जबकि प्राकृतिक खेती से भूमि की उर्वरता, जैविक कार्बन और भूजल भंडारण में वृद्धि होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन' के माध्यम से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिए जाने की जानकारी भी राज्यपाल ने दी।

एक समाचार पत्र द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 105 माताओं के दूध में कीटनाशकों के अंश पाए जाने का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने इस विषय को अत्यंत गंभीरता से लेने का आह्वान किया।

आतंक के प्रतीकों का अंत; लोकतंत्र की निर्णायक विजय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पुलिस बल का अभिनंदन

गडचिरोली। गडचिरोली जिले में माओवादियों के आतंक के प्रतीक के रूप में निर्मित शेष अंतिम 44 स्मारकों को सुरक्षा बलों द्वारा सफलतापूर्वक ध्वस्त किए जाने से जिले में माओवाद विरोधी संघर्ष को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इस कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 'एक्स' इस समाजमाध्यम के माध्यम से गडचिरोली पुलिस बल का हृदय से अभिनंदन किया है तथा कहा है कि यह कार्रवाई केवल भौतिक संरचनाओं को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कई वर्षों से जनता के मन में व्याप्त भय पर लोकतंत्र द्वारा प्राप्त की गई निर्णायक विजय है।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि दुर्गम और अतिदुर्गम क्षेत्रों में माओवादियों द्वारा स्थापित ये स्मारक स्थानीय नागरिकों में आतंक फैलाने और अपने अस्तित्व का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से खड़े किए गए थे। किंतु शासन की सतत एवं दृढ़ माओवाद विरोधी नीति के कारण गडचिरोली की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। सुरक्षा कार्रवाइयों, प्रभावी आत्मसमर्पण नीति, आधारभूत विकास परियोजनाओं तथा स्थानीय नागरिकों के बढ़ते विश्वास के चलते जिले का वातावरण सकारात्मक दिशा में परिवर्तित हो रहा है।

इस संयुक्त अभियान में गडचिरोली पुलिस बल, सी-60 कमांडो, सीआरपीएफ तथा विशेष दस्तों के लगभग 800 जवानों ने योजनाबद्ध खोज एवं जांच अभियान संचालित किया। बीडीडीएस दस्ते की गहन जांच के पश्चात विभिन्न वन क्षेत्रों में स्थित 44 स्मारकों को नेस्तनाबूत किया गया। एटापल्ली, हेडरी, भामरागड, जिमलगट्टा, धानोरा और पेंढरी उपविभागों के अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में यह कार्रवाई सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

जहां पहले आतंक के प्रतीक खड़े थे, वहां अब प्रशासन पर विश्वास, सुरक्षा की भावना और विकास की आशा सुदृढ़ होती दिखाई दे रही है। यह कार्रवाई गडचिरोली के बदलते यथार्थ का प्रतीक मानी जा रही है तथा भय से विश्वास की ओर और हिंसा से विकास की ओर हो रहे संक्रमण का यह एक महत्वपूर्ण चरण है, ऐसा मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में उल्लेख किया है।

राजधानी में शिवजयंती का समारोह अभूतपूर्व उत्साह के साथ

भारतीय सेना की मानवंदना और शिवराय के जयघोष से महाराष्ट्र सदन गूंज उठा

मुंबई। 'जय भवानी, जय शिवाजी' के गगनभेदी जयघोष, ढोल-ताशों की गूंज, तुतारियों की निनाद और शाहीरी पोवाड़ों की संगत में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज देश की राजधानी में अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भारतीय सेना की टुकड़ी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को विशेष मानवंदना दी।

दिल्ली स्थित शिवजयंती राष्ट्रोत्सव समिति की ओर से कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित नवीन महाराष्ट्र सदन में इस समारोह का आयोजन किया गया था। संभाजीराजे छत्रपति की प्रमुख उपस्थिति में तथा सांसद विशाल पाटील, निवासी आयुक्त एवं सचिव आर. विमला, निवास आयुक्त (गुंतवणूक) सुशील गायकवाड और सूचना निदेशक हेमराज बागुल के करकमलों से छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव, पालना पूजन और प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित किया गया।

इस अवसर पर शिवजयंती राष्ट्रोत्सव समिति, नवी दिल्ली द्वारा तैयार किए गए 'शिवकालीन दर्शिका 2026' कैलेंडर का प्रकाशन संभाजीराजे छत्रपति के हाथों किया गया। इस कैलेंडर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से लेकर निर्वाण तक घटित ऐतिहासिक घटनाओं का तिथिवार विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। नाशिक के शिवराय ढोल दल, लेझीम, वारकरी दिंडी और ध्वज दल की गूंज के बीच महाराष्ट्र सदन परिसर में भव्य 'शिव-शोभायात्रा' निकाली गई।

इस कार्यक्रम में सहायक निवासी आयुक्त नितीन शेंडे, सहायक निवासी आयुक्त स्मिता शेलार, जनसंपर्क अधिकारी मनीषा पिंगळे, उप अभियंता किरण चौधरी, प्रबंधक आशुतोष द्विवेदी और प्रमोद कोलपते, मुख्य सुरक्षा अधिकारी अनिल चोरगे सहित महाराष्ट्र सदन एवं परिचय केंद्र के कर्मचारी तथा दिल्ली के साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों से आए मराठी बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मुंबई उच्च न्यायालय का सफल न्यायनिर्णय; 79 वर्ष पुराना वाद समाप्त

मुंबई। मुंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक चरण प्राप्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात अर्थात 7 ऑक्टोबर 1947 को दायर किया गया एक दीवानी वाद पूरे 79 वर्ष बाद समाप्त किया गया है। न्यायमूर्ति फरहान पी. दुबाश ने 5 फेब्रुवारी 2026 को इस प्रकरण पर अंतिम निर्णय प्रदान किया।

यह वाद दिवंगत हाजी अलीमोहम्मद हाजी कासम अगबोटवाला की संपत्ति के विभाजन से संबंधित था। इस संपत्ति में मुंबई के संपूर्ण दहिसर ग्राम का समावेश था, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2,891 एकड़ था।

संपत्ति की देखरेख हेतु न्यायालय ने 1950 में 'न्यायालय अभिरक्षक' की नियुक्ति की। इसके अतिरिक्त 1952 में न्यायालय ने प्रारंभिक आदेश जारी कर सभी उत्तराधिकारियों के विधिक हिस्से निर्धारित किए। पिछले आठ दशकों में मूल पक्षकारों का निधन हो गया और उनके उत्तराधिकारी न्यायालय में संघर्ष करते रहे। वर्तमान में इस वाद में दिवंगत की चौथी पीढ़ी सक्रिय थी।

दीर्घकालीन विधिक संघर्ष के पश्चात चौथी पीढ़ी के सभी उत्तराधिकारियों ने एकजुट होकर 'परस्पर सहमति की शर्तें' स्वीकार कीं। न्यायालय ने इन शर्तों को मान्यता देते हुए वाद का निस्तारण किया। इस निर्णय के साथ मुंबई उच्च न्यायालय के इतिहास में सर्वाधिक दीर्घ अवधि तक लंबित रहने वाले प्रकरणों में से एक का समापन हुआ।

एमएमआरडीए के माध्यम से ठाणे-कल्याण का कायापालट : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

ठाणे को 'मोबिलिटी हब' तथा कल्याण को 'उन्नत शहरी केंद्र' के रूप में विकसित किया जाएगा- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई महानगर प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने तथा बढ़ते शहरीकरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एमएमआरडीए की बैठक में 48 हजार कोटी रुपये के अर्थसंकल्प को मंजूरी दी गई है। इसके माध्यम से ठाणे और कल्याण–इन दोनों शहरों का कायापालट होगा, ऐसी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी। उन्होंने बताया कि ठाणे को 'मोबिलिटी हब' के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि कल्याण भविष्य का उन्नत शहरी केंद्र बनेगा।

ठाणे शहर को मुंबई का महत्वपूर्ण प्रवेशद्वार मानते हुए यहां 12 से 13 हजार कोटी रुपये की बड़ी तरतूद की गई है। इसमें लगभग 12 किमी लंबाई वाले ठाणे-बोरीवली दोहरे सुरंग जैसे महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 2026-27 इस वर्ष हेतु 3 हजार कोटी रुपये की तरतूद की गई है, जिसे कुल 18 हजार 838 कोटी रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

इसके साथ ही ठाणे में मेट्रो नेटवर्क का

विकास किया जा रहा है। कासारवडवली से वडाला मेट्रो 4, मेट्रो 4-ए (गायमुख तक विस्तार) तथा स्वामी समर्थ नगर से विक्रोली मेट्रो 6 जैसी परियोजनाओं से ठाणे-मुंबई संपर्क व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। ठाणे कोस्टल रोड के प्रथम चरण के लिए 1 हजार 25 कोटी तथा आनंदनगर-साकेत उन्नत मार्ग के लिए 880 कोटी रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त रायलादेवी और मासुंदा तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ कोलशेत-काल्हेर खाड़ी पुल हेतु 214 कोटी रुपये की तरतूद की गई है, ऐसा उपमुख्यमंत्री शिंदे ने बताया।

भविष्य के नियोजित शहरी केंद्र के रूप में कल्याण-डोंबिवली क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए 2,500 से 3,500 कोटी रुपये की तरतूद की गई है। शहर में यातायात जाम दूर करने हेतु 1,239 कोटी रुपये की लागत वाले कल्याण रिंग रोड परियोजना के लिए 600 कोटी रुपये निर्धारित किए गए हैं। भिवंडी-कल्याण मेट्रो 5, उल्हासनगर विस्तार 5-ए तथा कांजूरमार्ग-बदलापुर मेट्रो 14 के कारण कल्याण एमएमआर का महत्वपूर्ण 'ट्रांजिट हब' बनेगा। ऐरोली-काटई नाका मार्ग 584 कोटी रुपये की इस परियोजना से नवी मुंबई के साथ संपर्क और अधिक मजबूत होगा, ऐसा भी उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा।

एमएमआर क्षेत्र के नागरिकों की जल समस्या के समाधान के लिए उपमुख्यमंत्री ने युद्धस्तर पर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में जल संकट दूर करने हेतु 'पोशीर' और 'शिलार'–इन दोनों बांधों के कार्यों को त्वरित गति देने के निर्देश उन्होंने दिए।

एमएमआर क्षेत्र में बढ़ती यातायात भीड़ को कम करने के लिए 337 किमी मेट्रो नेटवर्क के साथ पॉड टैक्सी, बोट टैक्सी, मल्टीमोडल संपर्क व्यवस्था, फ्लायओवर, भूमिगत सड़कें तथा बड़े आधारभूत परियोजनाओं का समन्वित खाका लागू किया जा रहा है, ऐसा उपमुख्यमंत्री शिंदे ने बताया।

'विकसित महाराष्ट्र' के लिए आधारभूत संस्थाओं की ठोस दिशा: ग्लोबल इकॉनॉमिक कोऑपरेशन परिषद में विकास दृष्टि प्रस्तुत

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। विदेश कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित ग्लोबल इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन परिषद में महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण आधारभूत एवं औद्योगिक संस्थाओं के प्रमुखों ने राज्य के उद्योग विकास, निवेश वृद्धि और 'विकसित महाराष्ट्र' के लक्ष्य की पूर्ति हेतु ठोस दिशा प्रस्तुत की।

मुंबई में आयोजित ग्लोबल इकॉनॉमिक कोऑपरेशन परिषद में विशेष परिचर्चा सत्र का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल के उपाध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक अनिलकुमार गायकवाड़, शहर एवं औद्योगिक विकास महामंडल के प्रबंध निदेशक विजय सिंघल, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार तथा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के मुख्य निवेश एवं योजना अधिकारी डॉ. शंकर देशपांडे ने सहभाग लेकर राज्य में चल रहे तथा प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की जानकारी दी।

इस अवसर पर उद्योग वृद्धि के लिए आधुनिक आधारभूत सुविधाएं, तीव्र और समन्वित संपर्क व्यवस्था, एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से उद्योग सुगमता तथा अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने हेतु किए जा रहे समझौता ज्ञापन महत्वपूर्ण घटक सिद्ध हो रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा सेंटर क्षेत्र की संभावनाएं, औद्योगिक समूह विकास, लॉजिस्टिक सक्षमता और कौशल विकास जैसे विषयों पर भी परिषद में गहन चर्चा हुई।

राज्य में प्रारंभ प्रमुख परियोजनाओं में नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय विमानतल, अटल सेतु और हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग जैसे उपक्रमों के कारण उद्योगों को सुगम संपर्क उपलब्ध होकर निवेश को प्रोत्साहन मिल रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। साथ ही एमएमआरडीए, सिडको, एमआईडीसी और एमएसआरडीसी के माध्यम से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों के कारण राज्य में रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति को गति मिल रही है, यह भी उन्होंने उल्लेख किया।

इस परिषद में प्रस्तुत विचारों के माध्यम से राज्य शासन के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर उद्योगों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने पर बल दिया गया। आधारभूत सुविधाओं, प्रौद्योगिकी, सतत विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के बल पर महाराष्ट्र उद्योग, नवाचार और आर्थिक प्रगति की दिशा में और अधिक तीव्र गति से अग्रसर होगा, ऐसा विश्वास मान्यवरों ने व्यक्त किया।

मुंबई उपनगर जिला : छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर भव्य पदयात्रा उत्साहपूर्वक संपन्न

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। मुंबई उपनगर जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय, जिला प्रशासन मुंबई उपनगर जिला तथा माय भारत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भव्य पदयात्रा उत्साहपूर्ण एवं प्रेरणादायी वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

वांद्रे स्थित जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिवराय के पराक्रम पर आधारित प्रभावशाली पथनाट्य, मर्दानी एवं पारंपरिक खेलों की प्रस्तुति तथा ढोल-ताशों की गूंज के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी सौरभ कटियार तथा निवासी जिलाधिकारी सतीश बागल की प्रमुख उपस्थिति रही।

पदयात्रा में नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल सर्विस स्कीम, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, विभिन्न लेझीम दलों के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने बड़ी संख्या में सहभाग किया। इस उपक्रम के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रप्रेम, शौर्य तथा सामाजिक एकता का प्रेरणादायी संदेश दिया गया।

शादी की रस्म के दौरान खूनी संघर्ष, मामूली विवाद में हुई तीन लोगों की हत्या; आरोपी गिरफ्तार

मुंबई। महाराष्ट्र के धुले जिले में एक शादी समारोह की खुशियां मातम में बदल गईं। यहां परिवार में हल्दी की रस्म के दौरान बाराती और घराती के बीच किसी बात को लेकर हिंसक हो गई। इस बहस के दौरान बारातियों की तरफ से कुछ युवकों ने दुल्हन के परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला किया। इस मारपीट में दुल्हन पक्ष के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए।

पुलिस ने क्या कहा?

एक पुलिस अधिकारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, यह घटना बुधवार को गुजरात-महाराष्ट्र बॉर्डर के पास साकरी तहसील के पिंपलनेर गांव में हुई। शादी से पहले हल्दी के कार्यक्रम के दौरान बाराती और घराती के बीच किसी छोटी सी बात पर बहस शुरू हुई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि तीन लोगों की हत्या कर दी गई।

क्या बोले मृतक के परिजन?

मृतकों की पहचान सुरेश गोसावी (50), साहिल गोसावी (35) और देवेंद्र (36) पवार के रूप में हुई है। इस घटना में पंकज अशोक गिर, सुरेश सुपदुगीर और सागर गोसावी घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने जानबूझकर जानलेवा हमला किया गया है।

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कांतिलाल गोसावी (42), जसवंत गोसावी (36) और उनका ड्राइवर एक ब्रेजा कार में सवार होकर गुजरात की ओर भाग निकले। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और स्थानीय लोगों से ओटाबारी घाट सेक्शन पर सड़क ब्लॉक करने की अपील की। साथ ही लोगों से संदिग्ध गाड़ी का नंबर नोट करने को भी कहा गया।

आरोपी हुए गिरफ्तार

इसके बाद कार को पहचान लिया गया और गुजरात-नवापुर बॉर्डर पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से एक छोटा चाकू भी मिला है। पकड़े गए तीनों आरोपी गुजरात के सोनगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि फिलहाल इलाके में हालात पूरी तरह नियंत्रण में और शांतिपूर्ण हैं।

सम्पादकीय

रोबोडॉग से परेः भारतीय उच्च शिक्षा का खोखलापन

गलगोटिया यूनिवर्सिटी में रोबोडॉग के प्रदर्शन से जुड़ा हालिया विवाद सोशल मीडिया और मुख्यधारा मीडिया में व्यापक चर्चा का विषय बना। सतह पर यह मामला उपयुक्तता, प्राथमिकताओं या कैंपस संस्कृति से जुड़ा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में वर्षों से पनप रहे एक गहरे और संरचनात्मक संकट का केवल एक लक्षण है। समस्या रोबोडॉग नहीं है। समस्या यह है कि हमारे विश्वविद्यालय धीरे-धीरे क्या बनते चले गए हैं।

पिछले दो दशकों में भारत में उच्च शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। निजी विश्वविद्यालयों, स्ववित्तपोषित कॉलेजों और डिग्री संस्थानों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। इस विस्तार को अक्सर 'शिक्षा तक पहुँच बढ़ने' और 'जनसांख्यिकीय लाभ' के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन जब यह विस्तार समानांतर नियमन, अकादमिक कठोरता और जवाबदेही के बिना हुआ, तो इसकी क़ीमत गुणवत्ता को चुकानी पड़ी। परिणाम यह हुआ कि मात्रा बढ़ी, पर गुणवत्ता लगातार गिरती चली गई।

आज देश के अधिकांश–हालाँकि सभी नहीं–निजी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज शिक्षा के केंद्र कम और डिग्री वितरण केंद्र अधिक बन गए हैं। शिक्षा एक बौद्धिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लेन-देन बनती जा रही है–पैसे के बदले डिग्री। उपस्थिति, अकादमिक भागीदारी, प्रयोगशाला कार्य और बौद्धिक अनुशासन जैसी बातें अब अनिवार्य नहीं रहीं, बल्कि समझौते के दायरे में आ गई हैं। जो कभी उच्च शिक्षा में गैर-समझौतावादी हुआ करता था, वह अब लचीला, कमजोर और विकृत हो चुका है।

यह गिरावट विशेष रूप से उन विषयों में चिंताजनक है जहाँ कठोरता अनिवार्य है। सैद्धांतिक पढ़ाई का कमजोर होना एक बात है, लेकिन विज्ञान शिक्षा का खोखला हो जाना कहीं अधिक गंभीर है। आज स्थिति यह है कि छात्र बिना नियमित कक्षाओं में गए और बिना प्रयोगशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण लिए विज्ञान जैसे विषयों में स्नातक और परास्नातक डिग्रियाँ प्राप्त कर रहे हैं। प्रयोगात्मक कार्य–जो कभी वैज्ञानिक प्रशिक्षण की रीढ़ हुआ करता था–अब औपचारिकता बनकर रह गया है। डिग्रियाँ तो दी जा रही हैं, लेकिन दक्षता सुनिश्चित नहीं की जा रही।

इस खोखलेपन के परिणाम तब स्पष्ट होते हैं जब छात्र नौकरी के लिए सामने आते हैं। रसायन विज्ञान में परास्नातक छात्र बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणाएँ नहीं समझा पाता। कॉमर्स स्नातक डेबिट और क्रेडिट की मूल अवधारणा स्पष्ट नहीं कर पाता। प्रबंधन की डिग्री रखने वाला छात्र समस्या-समाधान और आलोचनात्मक सोच में कमजोर दिखाई देता है। ये कोई इक्का-दुक्का उदाहरण नहीं, बल्कि उद्योग जगत द्वारा बार-बार देखी जा रही सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं।

स्वाभाविक रूप से इससे छात्रों और अभिभावकों में निराशा पैदा होती है। वर्षों की पढ़ाई और भारी आर्थिक निवेश के बावजूद जब रोजगार नहीं मिलता, तो सवाल उठते हैं। माता-पिता यह पूछने में बिल्कुल सही होते हैं कि पढ़ाई के बाद भी बच्चा बेरोज़गार क्यों है। अक्सर इस असंतोष का निशाना सरकार बनती है, जिस पर रोजगार सृजन न कर पाने का आरोप लगाया जाता है। हालाँकि रोजगार सृजन एक नीतिगत चुनौती है, लेकिन यह विमर्श एक असहज सच्चाई को नज़रअंदाज़ कर देता है–कि बड़ी संख्या में स्नातक वास्तव में रोजगार-योग्य ही नहीं हैं।

यहीं से मूल प्रश्न जन्म लेता है। यदि छात्रों में आवश्यक ज्ञान और कौशल नहीं है, तो उन्हें योग्य घोषित करने वाली डिग्रियाँ उन्हें कैसे मिल गईं? ऐसी संस्थाओं को बिना अकादमिक गुणवत्ता सुनिश्चित किए प्रमाणपत्र बाँटने की अनुमति किसने दी? इसका उत्तर हमें उच्च शिक्षा के नियामक ढाँचे में मिलता है।

भारत में उच्च शिक्षा की देखरेख कई मंत्रालयों, विभागों और नियामक संस्थाओं द्वारा की जाती है, जिनका घोषित उद्देश्य मानकों की रक्षा, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और अकादमिक ईमानदारी बनाए रखना है। मान्यता प्रणालियाँ, निरीक्षण, मूल्यांकन और अकादमिक ऑडिट इसी उद्देश्य से बनाए गए थे। लेकिन व्यवहार में ये प्रक्रियाएँ अक्सर वास्तविक मूल्यांकन की बजाय औपचारिक अनुष्ठान बनकर रह गई हैं।

निरीक्षण प्रायः पूर्व-निर्धारित होते हैं। दस्तावेज़ औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सजाए जाते हैं। इमारतों और बुनियादी ढाँचे को शिक्षण गुणवत्ता पर प्राथमिकता दी जाती है। अनुपालन को सीखने के परिणामों से ऊपर रखा जाता है। छात्रों का वास्तविक अकादमिक अनुभव, शिक्षण की गुणवत्ता, परीक्षा की कठोरता और जिज्ञासा की संस्कृति–इन पर गंभीर और निरंतर निगरानी शायद ही होती है। नतीजतन, संस्थान शिक्षा सुधारने के बजाय नियामकों को 'मैनेज' करना सीख लेते हैं।

इस नियामक शिथिलता ने एक दुष्चक्र को जन्म दिया है–संस्थान न्यूनतम अकादमिक जवाबदेही के साथ चलते रहते हैं, नियामक निगरानी का आभास बनाए रखते हैं, और डिग्रियाँ लगातार जारी होती रहती हैं। इस व्यवस्था की क़ीमत न तो संस्थान चुकाते हैं, न ही नियामक–बल्कि छात्र, नियोक्ता और समाज चुकाता है।

विडंबना यह है कि एक ओर उद्योग जगत योग्य मानव संसाधन की कमी की शिकायत करता है, वहीं दूसरी ओर देश शिक्षित बेरोज़गारी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। यह कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम है जहाँ प्रमाणपत्र को क्षमता से ऊपर रखा गया है। कंपनियाँ नए कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित करने पर भारी खर्च़ करने को मजबूर हैं, जबकि युवा पेशेवर आत्मविश्वास की कमी और करियर ठहराव से जूझते हैं। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा शिकार वे ईमानदार और प्रतिभाशाली छात्र हैं, जो अक्सर विकल्पों की कमी या भ्रामक ब्रांडिंग के कारण औसत संस्थानों में दाखिला ले लेते हैं। वे मेहनत करते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन अंततः उन्हें अपनी काबिलियत से ज़्यादा अपनी मार्कशीट पर दर्ज संस्थान के नाम का बोझ उठाना पड़ता है। उनकी व्यक्तिगत योग्यता संस्थागत विश्वसनीयता की कमी में दब जाती है। यह केवल अन्याय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा की बर्बादी है।

यह स्वीकार करना होगा कि भारत में आज भी कुछ उच्च-गुणवत्ता वाले संस्थान मौजूद हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन वे अपवाद हैं, नियम नहीं। उल्लेखनीय है कि बारहवीं तक की स्कूली शिक्षा आज भी अपेक्षाकृत अधिक संरचित और नियंत्रित है। जैसे ही छात्र उच्च शिक्षा में प्रवेश करता है, निगरानी ढीली पड़ जाती है और अपेक्षाएँ धुंधली हो जाती हैं।

स्वयं सहायता समूह से सशक्तिकरण तकः बड़वा की जूती की गूँज देशभर में

डॉ. प्रियंका सौरभ

हरियाणा की धरती परंपरा, परिश्रम और हुनर की अनमोल विरासत से समृद्ध रही है। यहाँ के गाँव केवल कृषि तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हस्तकला और पारंपरिक कौशल की जीवंत पहचान भी हैं। भिवानी जिले के सिवानी क्षेत्र के बड़वा गाँव की कारीगर कांता देवी ने इसी परंपरा को अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। आज उनकी बनाई हुई जूतियाँ गुरुग्राम में आयोजित सरस आजीविका मेले में ग्राहकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। यह सफलता केवल एक महिला की उपलब्धि नहीं, बल्कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और पारंपरिक कला के पुनर्जागरण की प्रेरक कहानी है।

कांता देवी का जीवन संघर्ष, समर्पण और संकल्प का उदाहरण है। उनका विवाह ऐसे परिवार में हुआ, जहाँ जूती निर्माण की कला पीढ़ियों से चली आ रही थी। उनके ससुर भाना राम इस पारंपरिक कार्य से जुड़े हुए थे और उनके पति भी इस काम में सक्रिय भूमिका निभाते थे। विवाह के बाद कांता देवी ने इस कला को केवल परंपरा के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाया। उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने का निश्चय किया और पूरी लगन से इसमें जुट गईं।

शुरुआत में कांता देवी गाँव में ही जूतियाँ बनाकर बेचती थीं। सीमित संसाधन, छोटा बाजार और कम आय जैसी कई चुनौतियाँ उनके सामने थीं। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके पति ने उनका पूरा सहयोग किया और गाँव में दुकान संभालकर इस व्यवसाय को मजबूत आधार दिया। यह पारिवारिक सहयोग उनकी सफलता की सबसे बड़ी ताकत बना। धीरे-धीरे उन्होंने अपने कौशल को निखारा और पारंपरिक डिजाइनों के साथ आधुनिक डिजाइनों को भी शामिल करना शुरू किया।

लगभग दस वर्ष पहले कांता देवी ने लक्ष्मीबाई महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया। इस समूह के माध्यम से उन्होंने गाँव की अन्य महिलाओं को भी इस कार्य से जोड़ा। यह पहल केवल रोजगार का माध्यम नहीं बनी, बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत उदाहरण भी बनी। इस समूह से जुड़कर महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता मिली और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। आज यह समूह कई महिलाओं के लिए स्थायी आय का स्रोत बन चुका है।

समय के साथ कांता देवी ने अपने उत्पादों को एक नई पहचान देने के लिए 'अभिनिक इंडिया' नाम से अपना ब्रांड स्थापित किया। यह कदम उनके व्यवसाय के विस्तार में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस ब्रांड के माध्यम से उनकी जूतियाँ स्थानीय बाजार से निकलकर बड़े शहरों और राष्ट्रीय स्तर के मेलों तक पहुँचने लगीं। उनके बेटे ने ऑनलाइन बिक्री की जिम्मेदारी संभाली, जिससे उनके उत्पाद डिजिटल प्लेटफॉर्म तक भी पहुँच गए। आज उनके पास 100 से अधिक डिजाइनों का संग्रह है, जो पारंपरिक कला और आधुनिक फैशन का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है।

उनकी जूतियों की कीमत 350 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक है और उनका मासिक कारोबार लगभग तीन लाख रुपये तक पहुँच चुका है। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि यदि ग्रामीण उत्पादों को सही मंच और अवसर मिले, तो वे आर्थिक रूप से अत्यंत सफल हो सकते हैं। यह सफलता केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान की भी कहानी है।

इस उपलब्धि में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और बाजार उपलब्ध कराया जाता है। इसी मंच के माध्यम से कांता देवी को सरस मेले में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिला। सरस मेला ग्रामीण कारीगरों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जहाँ उन्हें अपने हुनर को बड़े स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है।

भिवानी जिले के एक छोटे से गाँव से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचना आसान नहीं था। इसके पीछे वर्षों की मेहनत, परिवार का सहयोग और आत्मविश्वास की शक्ति थी। उनके ससुर भाना राम द्वारा शुरू की गई इस पारंपरिक कला को कांता देवी और उनके पति ने मिलकर आगे बढ़ाया और इसे आधुनिक पहचान दिलाई। यह परंपरा और नवाचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

इस सफलता का सामाजिक प्रभाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में उनका सम्मान भी बढ़ता है। वे परिवार के निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाने लगती हैं और अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में योगदान देती हैं। कांता देवी की सफलता ने गाँव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया है कि वे अपने कौशल का उपयोग कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

यह सफलता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब गाँव में ही रोजगार उपलब्ध होता है, तो लोगों को शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता कम हो जाती है। इससे ग्रामीण समाज में स्थिरता और समृद्धि आती है। यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हरियाणा जैसे राज्यों में पारंपरिक हस्तकला की अपार संभावनाएँ हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि इन कारीगरों को उचित प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराया जाए। यदि सरकार और सामाजिक संस्थाएँ मिलकर इस दिशा में कार्य करें, तो ग्रामीण हस्तकला न केवल देश में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकती है।

कांता देवी की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि मजबूत संकल्प और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि व्यक्ति अपने कौशल पर विश्वास रखे और मेहनत करे, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है।

आज कांता देवी केवल एक कारीगर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी हैं। उन्होंने यह दिखाया है कि पारंपरिक कला केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का आधार भी है। उनके पति और ससुर के सहयोग से शुरू हुई यह यात्रा आज राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है।

अंततः, बड़वा गाँव की जूतियों की यह सफलता केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की उपलब्धि है। यह कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि यदि ग्रामीण हुनर को सही मंच और सम्मान मिले, तो वह न केवल आर्थिक समृद्धि ला सकता है, बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत कर सकता है। कांता देवी की यह यात्रा आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपने हुनर पर गर्व करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहेगी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग तेज

अशोक मधुप

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित करने की मांग कोई नई नहीं है, बल्कि यह लगभग 70 वर्षों से चला आ रहा एक आंदोलन है। यह मांग केवल एक प्रशासनिक सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ एक गंभीर मुद्दा है। इस आंदोलन के कमजोर पड़ने का एक बड़ा कारण यह रहा कि आंदोलनरत वकील लंबे समय तक आम जनता को अपने साथ जोड़ नहीं पाए। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों ने अपनी इस कमी को समझते हुए रणनीति बदली है। वे अब आम जनता को इस आंदोलन से जोड़ रहे हैं, हाईकोर्ट बेंच के लाभ समझा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का समर्थन ले रहे हैं और उनसे केंद्र सरकार व विधि मंत्रालय को समर्थन पत्र लिखवा रहे हैं।

वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित की गई थी, लेकिन इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि लखनऊ भी इस क्षेत्र से काफी दूर है। वर्ष 1955 में विधि आयोग की सिफारिशों ने इस आंदोलन को नई दिशा दी। आयोग ने सुझाव दिया था कि जहां दूरी अधिक हो, वहां हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जानी चाहिए। उसी क्रम में 1955 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सम्पूर्णानंद ने मेरठ में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की सिफारिश की। 1976 में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने भी इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। जनता पार्टी शासनकाल में राम नरेश यादव की सरकार ने भी इस मांग का समर्थन किया। बनारसीदास सरकार और बाद में मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजे गए।

1970 और 1980 के दशक में यह आंदोलन और तेज हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों ने हड़तालों और प्रदर्शनों के माध्यम से इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। किसान नेता चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव और अजीत

सिंह जैसे नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया। इससे यह मांग एक राजनीतिक मुद्दा बनी, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और इलाहाबाद के वकीलों के दबाव के कारण यह अब तक पूरी नहीं हो सकी। आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न संगठन और बार एसोसिएशन इस मुद्दे पर लगातार आंदोलन करते रहते हैं।

मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा जैसे जिलों से इलाहाबाद की दूरी 500 से 700 किलोमीटर तक है। इतनी लंबी दूरी तय करने में वादियों और वकीलों को समय, पैसा और ऊर्जा तीनों खर्च करने पड़ते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह बेहद कठिन हो जाता है। यात्रा खर्च के साथ-साथ ठहरने और खाने का खर्च भी जुड़ जाता है, ऊपर से वकीलों की फीस अलग। इससे न्याय आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाता है। यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इलाहाबाद के बजाय लखनऊ बेंच से जोड़ा जाता, तब भी दूरी लगभग 200 किलोमीटर कम हो सकती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पर पहले से ही मुकदमों का भारी बोझ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले मामलों की संख्या अधिक होने से न्याय में देरी होती है। यदि यहां एक अलग बेंच स्थापित की जाए, तो मामलों का निस्तारण तेजी से होगा और न्यायपालिका पर दबाव भी कम होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश देश का एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है, जिसे अक्सर 'भारत का शुगर बाउल' कहा जाता है। यहां हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से इस क्षेत्र की न्यायिक और राजनीतिक पहचान मजबूत होगी और यह क्षेत्र अधिक आत्मनिर्भर बन सकेगा।

यह आंदोलन आज भी जारी है, हालांकि बीच-बीच में इसकी गति धीमी पड़ती रही है। वर्ष 1981 से वकील संगठनों द्वारा हर शनिवार हड़ताल, धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने का सिलसिला चलता आ रहा है। इसके बावजूद आंदोलन के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस मांग को टालती रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील भी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेंच बनने से उनके काम और आय पर असर पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि नई बेंच स्थापित करने से प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ेंगी और वित्तीय बोझ पड़ेगा। मजबूत और एकजुट नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर भी पड़ा है, क्योंकि अलग-अलग संगठन अलग-अलग तरीके से आंदोलन चला रहे हैं।

हाल ही में सांसद अरुण गोविल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सरकार लगभग छह करोड़ की आबादी वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में हाईकोर्ट की चार बेंच हैं, मध्य प्रदेश में दो बेंच हैं, लेकिन इतने बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में केवल एक ही बेंच है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय पाने में भारी कठिनाई होती है। यहां बेंच बनने से समय और धन दोनों की बचत होगी और पूरे राज्य की न्याय व्यवस्था मजबूत होगी।

1 अगस्त को जब पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में बॉम्बे हाईकोर्ट की चौथी बेंच स्थापित करने की अधिसूचना जारी हुई, तो मेरठ में उत्साह की लहर दौड़ गई। 'पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति' ने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के बार अध्यक्षों और महासचिवों की बैठक बुलाई। समिति ने सरकार से सवाल किया कि जब कोल्हापुर में चौथी बेंच खुल सकती है, तो मेरठ में तीसरी बेंच क्यों नहीं? इसके बाद 4 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। मुरादाबाद की सांसद कुंवरानी रुचिवीरा ने संसद में और चांदपुर से विधायक स्वामी ओमवेश ने विधानसभा में इस मांग को उठाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनप्रतिनिधियों ने इस मांग का समर्थन किया है।

लगभग 70 वर्षों से चला आ रहा यह आंदोलन कब तक चलेगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील आम जनता और जनप्रतिनिधियों को जोड़कर आंदोलन को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसके लाभों को सामने रखकर समर्थन जुटा रहे हैं और आंदोलन को नया स्वरूप देने में लगे हैं।

पारदर्शिता की पहल, लेकिन एकरूपता की कमी से कर्मचारियों की न्यायालय तक पहुंच बढ़ रही है

डॉ. सत्यवान सौरभ

हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर नीति प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण और साहसिक कदम है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के तबादलों में मनमानी, पक्षपात और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रही हैं। इन समस्याओं को समाप्त करने और प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष व मेरिट-आधारित बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि कर्मचारियों की वरिष्ठता, सेवा अवधि और विशेष परिस्थितियों के आधार पर उन्हें समान रूप से कार्यस्थल आवंटित किए जाएँ और किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो।

यह नीति आधुनिक प्रशासनिक सोच और प्रौद्योगिकी के उपयोग का एक सकारात्मक उदाहरण है। 50 या उससे अधिक पदों वाले कैडरों पर लागू यह प्रणाली 80 अंकों की मेरिट-आधारित मूल्यांकन व्यवस्था स्थापित करती है। आयु और कुल सेवा अवधि इसके प्रमुख मानदंड हैं, जिससे वरिष्ठता को उचित महत्व मिलता है। सेवा अवधि को 365 दिनों से विभाजित कर अंक निर्धारित किए जाते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी बनती है। महिला कर्मचारियों को 10 अंक, दंपती मामलों में 5 अंक तथा गंभीर बीमारी या दिव्यांगता की स्थिति में 10 से 20 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं।

पूरी प्रक्रिया मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ष्िए) से जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होती है। अधिसूचना जारी होने के बाद कैडर सूची सार्वजनिक की जाती है और कर्मचारी एक-बार उपयोग होने वाले पासवर्ड (ध्ऊइ) के माध्यम से सत्यापन कर अपनी पसंद के कार्यस्थल चुनते हैं। निर्धारित समय के भीतर विकल्प प्रस्तुत न करने की स्थिति में कर्मचारी को किसी भी स्थान पर पदस्थ किया जा सकता है। अधिशेष पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण अनिवार्य होता है और आदेश जारी होने की तिथि से निर्धारित समय के भीतर उन्हें कार्यभार ग्रहण करना होता है।

नीति लागू होने के बाद कई विभागों में पारदर्शिता बढ़ी है और शिकायतों में भी कमी आई है। ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली ने कर्मचारियों को अपनी बात रखने का मंच दिया है। इससे यह विश्वास मजबूत हुआ है कि डिजिटल प्रणाली के माध्यम से प्रशासनिक सुधार प्रभावी ढंग से लागू किए जा सकते हैं। हालाँकि, नीति के क्रियान्वयन में एकरूपता का अभाव इसकी सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। सभी विभागों में एक समान कार्यकाल, एक समान समय-सारिणी और एक समान नियम लागू नहीं हैं। कहीं न्यूनतम कार्यकाल अलग है, कहीं अधिकतम कार्यकाल की सीमा भिन्न है और कहीं विशेष परिस्थितियों की परिभाषा अलग-अलग है। इससे समान कैडर के कर्मचारियों के बीच असमानता उत्पन्न होती है और नीति की मूल भावना कमजोर पड़ती है।

यह अत्यंत आवश्यक है कि ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव की पहली ही प्रक्रिया में सभी कर्मचारियों की एक-बार अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यदि प्रारंभिक चरण में किसी कारणवश कुछ कर्मचारी बाहर रह जाते हैं, तो उनकी कार्यस्थल वरिष्ठता प्रभावित होती है और भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए 'एक-बार अनिवार्य भागीदारी' से सभी कर्मचारियों को समान स्तर पर लाना जरूरी है।

निर्धारित कार्यकाल सभी विभागों में समान होना चाहिए। उदाहरण के लिए, न्यूनतम कार्यकाल एक वर्ष या एक ट्रांसफर अभियान से अगले अभियान तक और अधिकतम कार्यकाल पाँच वर्ष तय किया जा सकता है। इससे न तो कोई कर्मचारी अत्यधिक लंबे समय तक एक ही स्थान पर बना रहेगा और न ही किसी को कम अवधि में बार-बार स्थानांतरण का सामना करना पड़ेगा। जब भी कोई नई नियुक्ति की जाए, उसे अगले ट्रांसफर अभियान में शामिल किया जाना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी अब तक ऑनलाइन ट्रांसफर नीति में शामिल नहीं हुआ है, तो उसे वर्तमान अभियान में ही सम्मिलित किया जाए। इससे सभी कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर पदस्थापन का अवसर मिलेगा और मनमाने या रिश्वत के माध्यम से पारंपरिक आदेशों द्वारा पोस्टिंग लेने की प्रवृत्ति समाप्त होगी।

सभी विभागों में ट्रांसफर अभियान एक साथ पूरे किए जाने चाहिए। इससे दंपती मामलों में निर्णय-प्रक्रिया सुगम होगी और परिवारों में अनिश्चितता कम होगी। यदि अलग-अलग विभाग अलग-अलग समय पर तबादले करते हैं, तो पारिवारिक समन्वय कठिन हो जाता है।

कार्यकाल की गणना करते समय दिनों की गणना के बजाय वित्तीय वर्ष को एक इकाई माना जाना चाहिए। कई बार ट्रांसफर प्रक्रिया वित्तीय वर्ष के मध्य में पूरी होती है और कार्यभार ग्रहण वर्ष के अंत में होता है, जिससे कार्यकाल की गणना में एक वर्ष का अंतर आ जाता है। यदि वित्तीय वर्ष को पूर्ण इकाई माना जाए, तो कट-ऑफ तिथि से जुड़े विवाद समाप्त हो सकते हैं।

ट्रांसफर अभियान हर वर्ष एक निश्चित और पूर्व-घोषित समय-सारिणी के अनुसार आयोजित किए जाने चाहिए। नियमित और वार्षिक तबादलों से कर्मचारियों की अनिश्चितता समाप्त होगी और प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा। अनियमित या विलंबित अभियानों से भ्रम और असंतोष उत्पन्न होता है।

पद पुनर्संरचना या युक्तिकरण की प्रक्रिया के दौरान, यदि अगली भर्ती प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी हो, तो न्यूनतम संख्या में पद अवरुद्ध किए जाने चाहिए, ताकि कर्मचारियों को अपने निवास के निकट कार्यस्थल मिलने की संभावना बढ़े। यदि युक्तिकरण एक बार व्यापक रूप से, सभी कर्मचारियों को शामिल करते हुए किया जाए, तो भविष्य में इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

वर्तमान में कई कर्मचारियों के नियुक्ति आदेशों में स्पष्ट रूप से 'अनिवार्य भागीदारी' लिखा है, लेकिन यदि कोई कर्मचारी किसी कारणवश भाग नहीं ले पाता, तो उसकी कार्यस्थल वरिष्ठता और अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी, यह स्पष्ट नहीं है। इस अस्पष्टता के कारण कई कर्मचारी प्रक्रिया से बाहर रह गए हैं, जिससे असमानता और असंतोष बढ़ा है।

सबसे गंभीर चिंता यह है कि ऑनलाइन नीति लागू होने के बाद भी कुछ तबादले पारंपरिक तरीकों से किए गए। यह स्थिति नीति की पारदर्शिता और निष्पक्षता के बिल्कुल विपरीत है। जब कुछ कर्मचारियों को अंकीय प्रणाली के आधार पर और कुछ को पारंपरिक आदेशों से पदस्थ किया जाता है, तो समान अवसर का सिद्धांत कमजोर पड़ता है। ऐसे समानांतर तंत्र नीति पर संदेह पैदा करते हैं और कर्मचारियों में भेदभाव की भावना उत्पन्न करते हैं।

इन विसंगतियों के कारण अनेक कर्मचारी न्यायालय का सहारा लेने को मजबूर हो रहे हैं। समान पद और समान सेवा अवधि के बावजूद भिन्न व्यवहार विवाद को जन्म देना स्वाभाविक है। न्यायालयी प्रक्रिया कर्मचारियों के लिए मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कष्टदायक होती है और प्रशासन पर भी अतिरिक्त बोझ डालती है।

यदि नीति को पूर्णतः एकरूप और अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, सभी कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और पारंपरिक तबादलों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए, तो न्यायालय जाने की आवश्यकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इससे कर्मचारियों का विश्वास बढ़ेगा और प्रशासनिक प्रणाली की विश्वसनीयता सुदृढ़ होगी।

मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर नीति एक दूरदर्शी पहल है, लेकिन इसकी सफलता पूर्ण पारदर्शिता, एकरूप नियमों और कड़े अनुपालन पर निर्भर करती है। जब तक सभी विभागों में समान कार्यकाल, एक समान वार्षिक समय-सारिणी, अनिवार्य भागीदारी और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही पदस्थापन सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक इसकी मूल भावना अधूरी ही रहेगी।

आज आवश्यकता है कि इस नीति को और अधिक स्पष्ट, मजबूत और सुसंगत बनाया जाए। यदि ऐसा किया जाता है, तो यह प्रणाली न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में सुशासन, पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रशासन का एक आदर्श मॉडल बन सकती है।

Viksit Bharat की ओर बड़ा कदम, Amit Shah असम में लॉन्च करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का दूसरा चरण

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को असम में जीवंत ग्राम कार्यक्रम (वीवीपी-II) के दूसरे चरण का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन 20 फरवरी को कछार जिले के नाथनपुर गांव में किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार, वीवीपी-छ्छ को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जाएगा, जिसके लिए वित्त वर्ष 2028-29 तक 6,839 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना 15 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के सीमावर्ती गांवों को कवर करेगी, जो रणनीतिक रूप से संवेदनशील और अक्सर दूरस्थ क्षेत्रों में समावेशी विकास पर सरकार के जोर को दर्शाती है।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वीवीपी-छ्छ को एक व्यापक पहल के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित गांवों का संतृप्ति-आधारित विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य आवश्यक बुनियादी ढांचे में सुधार करना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सड़क संपर्क और दूरसंचार जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करना

और स्थानीय निवासियों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना है।

इसमें कहा गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण 'विकसित भारत 2047' के अनुरूप सुरक्षित, लचीले और समृद्ध सीमावर्ती समुदायों का निर्माण करना है। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (न्न्ङ-छ्छ) का दूसरा चरण वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के पहले चरण की नींव पर आधारित है, जो मुख्य रूप से उत्तरी सीमावर्ती गांवों पर केंद्रित था। दूसरे चरण में इसका दायरा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है, जिनमें पूर्वोत्तर के क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां कनेक्टिविटी की चुनौतियां और विकास संबंधी कमियां ऐतिहासिक रूप से विकास में बाधा रही हैं।

अधिकारियों ने बताया कि यह योजना समन्वय-आधारित दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को एक साथ लाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचे। बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करके और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर, इस पहल का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों से पलायन को रोकना और स्थानीय आबादी को अपने मूल क्षेत्रों में बसे रहने के लिए प्रोत्साहित करना है।

विकास के अलावा, इस कार्यक्रम का एक रणनीतिक आयाम भी है। मजबूत और घनी आबादी वाले सीमावर्ती गांवों से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। निवासी सतर्क हितधारक के रूप में कार्य कर सकते हैं, राष्ट्र की आंखें और कान बनकर सीमा पार अपराधों, अवैध घुसपैठ और अन्य सुरक्षा खतरों को रोकने में सहायता कर सकते हैं।

वीरेंद्र सचदेवा बोले- दिल्ली मे 71 अटल कैंटीन खुले, पांच रुपये में मिल रहा गरीबों को भोजन

नई दिल्ली। भाजपा ने दिल्ली में अपना बड़ा वादा निभा दिया है। पार्टी ने चुनाव के दौरान दिल्ली की हर विधानसभा में अटल कैंटीन खोलने का वादा किया था। 70 विधानसभा क्षेत्रों वाली दिल्ली में अब तक 71 अटल कैंटीन खोली जा चुकी हैं जिनमें गरीबों को केवल पांच रुपये में भोजन दिया जा रहा है। इनमें से 25 अटल कैंटीन को गुरुवार को खोला गया। भाजपा का दावा है कि इन कैंटीनों में हर दिन हजारों गरीबों को भोजन कराया जा रहा है। इससे उनका

स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, साथ ही उन्हें बचत करने में भी सहायता मिलेगी।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को अटल कैंटीनों के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भाजपा नेताओं ने अटल कैंटीनों में गरीबों को मिलने वाले भोजन को जांचा और इसे सही गुणवत्ता का बताया। पार्टी ने कहा है कि आने वाले दिनों में कुछ अन्य प्रमुख स्थानों पर भी अटल कैंटीनें खोली जाएंगी।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि राजधानी में सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर वे अपना यह बड़ा वादा निभा रहे हैं। दिल्ली सरकार एवं संगठन की भागीदारी से दिल्ली में 71 कैंटीनों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर उसकी शुरुआत की गई। नेताओं ने जनता से बातचीत कर इनके बारे में उनकी राय जानी। वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि अटल कैंटीन की प्रेरणा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों से मिली है जिन्होंने हमेशा गरीब, श्रमिक और वंचित वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि इससे मेहनतकश मजदूरों, रिक्शा चालकों, दिहाड़ी श्रमिकों और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जहाँ उन्हें बहुत ही कम लागत में पौष्टिक भोजन सुलभ होगा।

फर्जी दस्तावेजों पर 255.75 करोड़ के ठेके, सीएजी ने यूपीसीडा की कार्यप्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल

लखनऊ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। विधानमंडल के दोनों सदनों में गुरुवार को पेश की गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो बिल्डर कंपनियों को 255.75 करोड़ रुपये के औद्योगिक विकास कार्यों के ठेके आवंटित कर दिए गए थे।

पुलिस मामले की जांच करती हुई।

यूपी में सनसनीखेज घटनाः बाराबंकी में किशोरी को जिंदा जलाया, दुष्कर्म की आशंका; ये सामान बरामद

सीएजी की यह रिपोर्ट वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि से संबंधित है। रिपोर्ट में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन, भूमि अधिग्रहण, बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन, भूमि विकास कार्यों, सार्वजनिक उपक्रमों को असुरक्षित ऋण देने तथा आयकर छूट का लाभ न लेने जैसे कई मामलों में अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015-16 में मेसर्स बालाजी बिल्डर को अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन किए बिना ही औद्योगिक क्षेत्रों के दो चयनित निर्माण खंडों के विकास के लिए 143.22 करोड़ रुपये के 13 अनुबंध प्रदान कर दिए गए।

बाद में जांच में अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए और वर्ष 2017 में अनुबंध निरस्त करने पड़े। इसी तरह मेसर्स आकाश इंजीनियरिंग एंड बिल्डर्स को अनुभव प्रमाण पत्र और एफडी के सत्यापन के बिना 112.53 करोड़ रुपये के दो अनुबंध दे दिए गए। वर्ष 2018 में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर ये अनुबंध भी निरस्त किए गए।

प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कराई गई

इस प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, लेकिन दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इसका उल्लेख रिपोर्ट में नहीं है। 12.65 करोड़ रुपये की देय राशि में से केवल 1.39 करोड़ रुपये ही वसूले जा सके। सीएजी ने स्पष्ट अनुशंसा की है कि ऐसे मामलों में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि विकास कार्यों से जुड़े ठेकों की बोली प्रक्रिया से पहले ठेकेदारों की तकनीकी और वित्तीय क्षमता का समुचित आकलन नहीं किया गया।

सीएए से जुड़े मामलों पर पांच मई से सुनवाई; स्टालिन के चुनाव को चुनौती मामले में फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली आईयूएमएल समेत 200 से ज्यादा याचिकाओं पर कहा कि इनकी अंतिम सुनवाई 5 मई से सुनवाई शुरू होगी। सीएए का मकसद हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदायों के उन प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से देश में आए थे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमालया बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने 2019-2020 से लंबित याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के संबंध में प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किए। पीठ ने कहा कि इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग आईयूएमएल के साथ अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर डेढ़ दिन तक सुनवाई करेगी। केंद्र को अपनी दलीलें पेश करने के लिए एक दिन का समय दिया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीठ 12 मई को याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर लेगी। पीठ ने पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज और दलीलें दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा कि वह पहले पूरे भारत में सीएए के लागू होने से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करेगी और उसके बाद असम और त्रिपुरा से संबंधित याचिकाओं पर ध्यान देगी।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एआईएडीएमके नेता सैदाई एस दुरैसामी की ओर से दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन के खिलाफ उनकी चुनाव याचिका खारिज कर दी गई थी। याचिका में स्टालिन पर 2011 के विधानसभा चुनावों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे।

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों की ओर से दी गई दलीलों को सुना। 2017 में मद्रास उच्च न्यायालय ने दुरैसामी की चुनाव याचिका खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि दुरैसामी 2011 के चुनावों में कोलाथुर सीट से स्टालिन से 2,739 वोटों से हार गए थे। दुरैसामी ने आरोप लगाया था कि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को निर्धारित व्यय सीमा से अधिक धनराशि बांटी गई और साथ ही पूरक मतगणना भी की गई। दुरैसामी ने डीएमके पर अपने पदाधिकारियों और धन का इस्तेमाल करके मतदाताओं को लुभाने के लिए नए-नए तरीके अपनाने का भी आरोप लगाया।

दोबारा विचार करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई से उस नियम पर दोबारा विचार करने को कहा, जिसके तहत बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को राज्य बार काउंसिल के चुनाव लड़ने से रोका जाता है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने वकील धन्या कुमार जैन की याचिका पर यह आदेश पारित किया और याचिका का निपटारा कर दिया। याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्ष 2016 के चुनावों के लिए बनाए गए समान नियमों और अनिवार्य दिशानिर्देशों को चुनौती दी गई थी। विवादित प्रावधान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को छोड़कर किसी भी बार एसोसिएशन का पदाधिकारी राज्य बार काउंसिल का चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा। नियम में यह भी कहा गया है कि संबंधित राज्य बार काउंसिल के चुनाव की अधिसूचना की तारीख को जो व्यक्ति किसी बार एसोसिएशन का पदाधिकारी था या है, उसका नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर खारिज कर देगा। अदालत के समक्ष यह तथ्य भी रखा गया कि राज्य बार काउंसिल एक वैधानिक संस्था है, जबकि बार एसोसिएशन किसी विशेष अदालत या अधिकरण में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के निजी संगठन होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट को बड़ा झटका देते हुए उसकी क्यूरेटिव (सुधारात्मक) याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि योग शिविरों के लिए एंट्री फीस लेने पर ट्रस्ट को सर्विस टैक्स देना होगा। इससे पहले शीर्ष अदालत ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा था।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस उज्जवल भुइंया की पीठ ने 4 फरवरी के आदेश में कहा कि क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि 2002 के रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा मामले में तय मानकों के अनुसार इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। इससे पहले 7 जनवरी 2024 को जस्टिस अभय एस ओका (सेवानिवृत्त) और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने पतंजलि ट्रस्ट की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी।

19 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के उस फैसले को सही ठहराया था, जिसमें कहा गया था कि आवासीय और गैर-आवासीय योग शिविरों के लिए ली जाने वाली एंट्री फीस पर सर्विस टैक्स लागू होगा। इस फैसले के खिलाफ पतंजलि ने क्यूरेटिव (सुधारात्मक) याचिका दाखिल की थी, जो अब खारिज हो चुकी है।

ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कोशिश या यूजीसी पर नाराजगी कम करने का प्रयास? बटुकों के सम्मान से उठे सवाल

नई दिल्ली। यूपी में ब्राह्मणों पर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को अपने आवास पर ब्राह्मण बटुकों का सम्मान किया जिसके बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि भाजपा अपने इस कोर वोट बैंक को लुभाने के लिए सक्रिय हो गई है। पहले प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद और बाद में यूजीसी को लेकर कहा जा रहा है कि प्रदेश का ब्राह्मण वर्ग भाजपा से नाराज है और आगामी चुनाव में वह गैर भाजपाई विकल्प तलाशने की कोशिश कर सकता है। इस कथित नाराजगी को भुनाने के लिए बसपा-सपा दोनों ही दल सक्रिय हो गए हैं जो इसी वर्ग के समर्थन के सहारे 2007 और 2012 में अपनी सरकार बना चुके हैं। इस राजनीतिक रस्साकसी के बाद यूपी में लगभग 11 फीसदी जनसंख्या वाला ब्राह्मण वर्ग किधर जा सकता है?

दरअसल, प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ग के नेता बनकर उभरे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि उन्होंने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर रखी है जिससे समाज का हर वर्ग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी ब्राह्मणों के भाजपा से नाराज होने की बातें कही गई थी, लेकिन अंततः योगी आदित्यनाथ एक बार फिर इस वर्ग की पसंद बनकर उभरे और योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रहे।

यूजीसी से मामला बिगड़ा

लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार मामला इतना सीधा-साधा नहीं है। भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा विश्वविद्यालयों में यूजीसी कानून लाने की कोशिश करने के बाद पार्टी का कोर वोटर वर्ग ब्राह्मण-ठाकुर-बनिया और लाला समुदाय उससे नाराज है। उसे लग रहा है कि अब कॉलेजों में भी भेदभाव के नाम पर उनके बच्चों को निशाना बनाया जा सकता है। इस आशंका से डरे सामान्य वर्ग में सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न कार्यक्रमों और विरोध प्रदर्शनों में सामान्य वर्ग की यह नाराजगी खुलकर सामने आ रही है।

भाजपा जानती है कि ब्राह्मण, राजपूत, बनिया और लाला उसका सबसे प्रबल समर्थक वर्ग रहा है। वह केवल उसे वोट ही नहीं देता, बल्कि हर मंच पर उसके लिए वैचारिक लड़ाई लड़ने का काम भी करता है। यदि इस वर्ग का समर्थन उससे दूर हो जाता है तो यूपी के साथ-साथ पूरे देश की राजनीति में टिकना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा।

ब्राह्मणों के दूर होने से खात्मे के कगार पर पहुंची कांग्रेस

ब्राह्मण वर्ग कभी कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था। ब्राह्मण, दलित और मुसलमानों के सहयोग से ही कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में बनी रही। लेकिन कांग्रेस की गलत नीतियों और भाजपा के राम मंदिर आंदोलन से आकर्षित होकर ब्राह्मण वर्ग कांग्रेस से छिटक कर भाजपा के पास चला गया। कांग्रेस इस नुकसान से आज तक उबर नहीं पाई और वह पहले सत्ता में आने के लिए दूसरे दलों पर निर्भर हुई और अंततः सत्ता से बाहर हो गई। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि भाजपा अपने इस कोर वोट बैंक को साधने में गलती करती है तो उसे इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

2024 के लोकसभा चुनाव में दलित मतदाताओं के एक छोटे वर्ग के दूर जाने का नुकसान उठा चुकी भाजपा भी इस सच को जानती है। माना जा रहा है कि यही कारण है कि पार्टी अपने इस कोर वोट बैंक को संभालने के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में डट गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 18 फरवरी को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। 19 फरवरी को मोहन भागवत ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्रियों ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से अलग-अलग मुलाकात की है। इस मुलाकात को भी यूपी की बदली सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि संघ इस पूरे घटनाक्रम को संभालने में जुट गया है।

सबका साथ, सबका विश्वास के साथ चलते हैं- भाजपा

उत्तर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता पल्लवी सिंह ने अमर उजाला से कहा कि उनकी पार्टी देश के हर समाज, हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रयास करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के हर वर्ग के साथ, सबके विश्वास और सबके विकास की बात करते हैं। यही कारण है कि समाज के हर वर्ग का भाजपा को समर्थन मिलता है और भाजपा की सरकारें हर राज्य में लगातार प्रो इनकमबेंसी फैक्टर के सहारे सत्ता में आ रही हैं।

पल्लवी सिंह ने कहा कि कुछ घटनाओं को लेकर सपा और कांग्रेस के नेता समझने लगते हैं कि अब यह वर्ग उनके पास आ जाएगा। लेकिन जनता ने अपने अनुभव से यह देखा है कि इन दलों की सरकारों में किस तरह एक खास वर्ग का तुष्टिकरण किया जाता था। गरीबों-महिलाओं की बजाय अपराधियों का संरक्षण किया जाता था। उन्होंने कहा कि इसी कारण प्रदेश की जनता लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में अपना भरोसा बनाए हुए है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा 2027 का विधानसभा चुनाव भी पूर्ण बहुमत से जीतेगी और जनता के भरोसे पर खरी उतरेगी।

योगी सरकार की कलई खुली- कांग्रेस

उत्तर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने कहा कि विकास का दावा करने वाली भाजपा सरकारों की कलई खुल गई है। भाजपा नेता दावा तो विकास का करते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता ने देख लिया है कि किस तरह वे पहले एक वर्ग विशेष से दूसरे वर्ग को भड़का कर सांप्रदायिक आधार पर अपनी राजनीति करते हैं। अब वे हिंदू समाज के अलग-अलग वर्गों को भी तोड़ने में जुट गए हैं।

विश्व विजय सिंह ने कहा कि आज ब्राह्मण बटुकों का सम्मान करने वाली भाजपा उस समय कहां थी जब प्रयागराज में इनका अपमान किया जा रहा था।

धीरेंद्र शास्त्री की पहली बार शहर में होने वाली कथा पर लगा 'ग्रहण', एलडीए ने आवंटन किया रद्द

लखनऊ। चर्चित कथा वाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की शहर में पहली बार होने वाली कथा पर ग्रहण लग गया है। अब यह नहीं हो पाएगी क्योंकि एलडीए ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उनका 9 से 18 मार्च का आवंटन ही बृहस्पतिवार को अचानक रद कर दिया है।

यह किस कारण हुआ है, इसको लेकर एलडीए और पुलिस के अफसर अधिकृत पर असली वजह नहीं बता रहे हैं मगर अंदरखाने की चर्चा गंभीर है। जिसमें बाबा की कथा से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की अंदेशा जताया जा रहा है क्योंकि एक समुदाय विशेष की आबादी ज्यादा और उस पर उनका पवित्र महीना भी शुरू हो गया है।

खास यह भी है कि सोशल मीडिया प्लेट फार्म फेसबुक पर बाबा ने यह ऐलान कर दिया है कि वह 14 से 18 मार्च तक लखनऊ में रहेंगे। वहां पर सुंदरकांड पाठ आधारित कथा करेंगे। इसमें एक दिन उनका दिव्य दरबार भी होगा। यह वह दरबार होता है जिसमें बाबा खुद ही बिना पूछे भक्तों की परेशानी और उनकी इच्छा के बारे में लिखकर पर्ची देते हैं, जिससे लोग खूब हैरान भी होते हैं।

अब जो हाल है उसमें न तो कथा होने के आसार हैं न दिव्य दरबार के। कथा का आयोजन कराने वाली संस्था हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के न्यासी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि आयोजन का लेकर पुलिस की अनुमति अभी नहीं मिली है। उसको लेकर वह प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कि वह पहले वृंदावन योजना के डिफेंस एक्सपो स्थल आयोजन करना चाह रहे थे।

वहां पर पुलिस न कहा कि कथा से शहीद पथ पर जाम लग सकता है ऐसे में इसे राष्ट्र प्रेरणा स्थल में किया जाना ठीक रहेगा। उसके बाद एलडीए में आवेदन किया और स्थल बुक कराया। पैसा जमा करने का पत्र भी मिला मगर पैसा जमा नहीं हो पाया। पुलिस से अनुमति को लेकर प्रयास किया जा रहा था मगर इसी बीच अब एलडीए से आवंटन निरस्त होने का पत्र मिला है। अब असली वजह क्या है यह तो अधिकारी जाने मगर आवंटन निरस्त करना सही नहीं है।

अधिकारियों ने कही ये बात

अधिशासी अभियंता एलडीए निशांत चंद्रा ने बताया कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर मरम्मत के काम होने हैं। इस कारण आवंटन निरस्त किया गया है। कोई खास वजह नहीं है।

यूपी में सनसनीखेज घटनाः बाराबंकी में किशोरी को जिंदा जलाया, दुष्कर्म की आशंका; ये सामान बरामद

बाराबंकी। बाराबंकी में मोहम्मदपुर खाला थाना परिसर से महज सौ मीटर की दूरी पर बृहस्पतिवार दोपहर 17 वर्षीय किशोरी को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। देर शाम उसने लखनऊ के सिविल अस्पताल के बर्न वार्ड में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

मौत से पहले पुलिस को दिए बयान में कस्बे के पेट्रोल पंप पर कार्यरत युवक का नाम लिया और कहा कि उसने ही कहा था कि फूंक देंगे। संवाद न्यूज एजेंसी के पास मौजूद वीडियो के अनुसार युवक का नाम लेने के बाद किशोरी की आवाज लड़खड़ाने लगी और वह आगे कुछ नहीं बोल सकी।

परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। मामले में दो से तीन लोगों के शामिल होने की आशंका जताई है। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार किशोरी के शरीर पर कपड़े नहीं थे। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आरोपी युवक की तलाश भी की जा रही है।

परिजनों के अनुसार, किशोरी दोपहर करीब 12 बजे घर से शौच के लिए निकली थी। लगभग 12:16 बजे बड़ी बहन के पास सूचना आई कि वह घर से करीब 150 मीटर दूर खेत में जली हालत में पड़ी है। बहन का कहना है कि जब परिवार सहित वह मौके पर पहुंची तो उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे।

पास के खेत में मचान पर पड़ी रजाई से उसे ढंका गया। वहीं, पुलिस के मुताबिक थाने के पीछे से धुआं उठता और चीख-पुकार सुनाई देने पर लोग दौड़कर पहुंचे। गंभीर रूप से झुलसी किशोरी को अस्पताल पहुंचाया गया। घटनास्थल से पेट्रोल व पानी की भी एक बोतल बरामद हुई है। करीब 80 प्रतिशत तक झुलस चुकी किशोरी ने एक पेट्रोल पंप कर्मचारी का नाम लिया है।

एसपी ने कही ये बात

एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि किशोरी के शरीर के कपड़े जल गए थे। घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। मामले की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान में हुई ऐसी गलती, सोशल मीडिया पर बन गया शहबाज शरीफ का मजाक

नई दिल्ली। पाकिस्तान का हाथ अंग्रेजी में भले ही तंग हो, लेकिन क्रिकेट के मैदान से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वो इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करता है। टी20 विश्वकप में भारत के हाथों करारी शिकस्त मिलने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा भी टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलते दिखे थे। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के हालिया बयान में एक छोटी सी गलती ने फिर से अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश को मजाक का पात्र बना दिया है।

पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय एक सामान्य सी घोषणा में अंग्रेजी की वर्तनी की गलती से जगहंसाई करवा बैठा। दरअसल, यह बयान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अमेरिका यात्रा को लेकर जारी किया गया था। इस बयान की पहली ही लाइन में युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को युनाइट्स स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज लिखा गया था।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान में क्या था?

बयान में शहबाज शरीफ की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर बोर्ड ऑफ पीस के उद्घाटन सत्र में भाग लेने के लिए आधिकारिक यात्रा पर जाने की घोषणा की गई थी। वैसे क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए ये आम बात है।

पाकिस्तान सरकार से इस तरह की उम्मीद नहीं ही की जाती है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब पाकिस्तानी सरकार ने भी गलत अंग्रेजी के लिए दुनिया में अपनी थू-थू करवाई हो।

इस्राइल के आलोचना में शहबाज कर बैठे थे बड़ी गलती

बीते साल अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक तनावपूर्ण मौके पर भी शहबाज शरीफ सोशल मीडिया पर कथित टाइपो को लेकर सुर्खियों में आए थे। इस्राइल की ओर से ईरान पर किए गए हवाई हमलों की निंदा करते हुए एक स्क्रीनशॉट में दावा किया गया था कि उन्होंने 'आई कंडेम द अटैक' की जगह 'आई कंडोम द अटैक' लिख दिया था।

शहबाज शरीफ की इन गलतियों को तुरंत पाकिस्तानी आवाम ने पकड़ लिया और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। इन छोटी गलतियों ने सोशल मीडिया पर गंभीर कूटनीतिक मुद्दों को मजाक और मीम्स में बदल डाला।

भिवंडी महानगरपालिका में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर किया गया अभिवादन

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका की ओर से गुरुवार को छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। महाराष्ट्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्रक के अनुसार 19 फरवरी 2026 को महानगरपालिका मुख्यालय के भूतल पर आयोजित कार्यक्रम में प्रशासक तथा आयुक्त अनमोल सागर (आईएएस) ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर उन्हें अभिवादन किया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी मराठा साम्राज्य के संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों को याद किया। कार्यक्रम में उप आयुक्त (मुख्यालय) विक्रम दराडे, उप आयुक्त (कर) बालकृष्ण क्षिरसागर, शहर अभियंता जमिल पटेल, उप आयुक्त सपना वसावा, अतिरिक्त शहर अभियंता सचिन नाईक, कार्यकारी अभियंता संदीप पटणावर (पानी आपूर्ति विभाग), सहायक आयुक्त स्वास्थ्य फैसल तातली, सहायक आयुक्त प्रभाग समिति क्रमांक 1 मकसुम शेख, प्रभाग समिति क्रमांक 2 माणिक जाधव, प्रभाग समिति क्रमांक 3 सुरेंद्र भोईर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेश पवार, मार्केट विभाग प्रमुख स्नेहल पुण्यार्थी, वाहन विभाग प्रमुख शेखर चौधरी, बी.जे.पी. दवाखाना कार्यालयीन अधीक्षक नितेश चौधरी, पर्यावरण विभाग प्रमुख सुनील भोईर, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक जे.एम. सोनावणे (पूर्व) और हरेश भंडारे (पश्चिम) सहित बड़ी संख्या में मनपा कर्मचारी उपस्थित रहे। मनपा की ओर से बताया गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों से प्रेरणा लेकर प्रशासन नागरिकों की सेवा और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है।

आईटी सिस्टम हैक कर अज्ञात ठग ने लगाया चूना

भिवंडी में साइबर ठगी का बड़ा खेल, फर्जी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से कंपनी खाते से लाखों उड़ाए

28 लाख से ज्यादा की ऑनलाइन धोखाधड़ी, पुलिस जांच में जुटी

भिवंडी। शहर में साइबर अपराध का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां अज्ञात साइबर ठग ने ऑनलाइन फर्जीवाड़ा कर कंपनी के बैंक खाते से लाखों रुपये उड़ा दिए। घटना के बाद कारोबारी वर्ग में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर ठग की तलाश शुरू कर दी है। भिवंडी शहर पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता संजीव रंगया अंकम (35), जो एक कंपनी के संचालक हैं, ने बताया कि 13 जनवरी दोपहर को पद्मानगर रोड स्थित अपने कार्यालय में मौजूद थे। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने कंप्यूटर सिस्टम और ऑनलाइन बैंकिंग प्रक्रिया का दुरुपयोग कर उनकी कंपनी के बैंक खाते से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 28 लाख 55 हजार 740 रुपये की रकम ट्रांसफर कर ली। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने फर्जी पहचान और तकनीकी तरीके अपनाकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को अंजाम दिया। पीड़ित को धोखाधड़ी का पता चलने के बाद तुरंत शहर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई गई।पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल साइबर सेल की मदद से बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल ट्रेल की जांच की जा रही है। इस प्रकरण की जांच पुलिस उप निरीक्षक ललित केदार कर रहे है।

भिवंडी में रफ्तार का कहर, डिवाइडर पार कर बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत

हिट एंड रन से सनसनी, मदद किए बिना फरार हुआ चालक

भिवंडी। शहर में तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक और जान ले ली। मुंबई-नाशिक हाईवे पर बुधवार शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे में डिवाइडर पार कर आए तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक घायल को तड़पता छोड़ मौके से फरार हो गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार यह घटना 18 फरवरी को शाम करीब 6:30 बजे की है। शिकायतकर्ता अक्षय आनंद सावंत (30) ने बताया कि उनका मित्र प्रताप सुरेश यादव (32) मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान अचानक डिवाइडर क्रॉस कर तेज रफ्तार से आए अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। आरोप है कि हादसे के बाद वाहन चालक बिना मदद किए मौके से फरार हो गया। नारपोली पुलिस स्टेशन में अज्ञात चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है।

रमजान के दौरान अस्थायी स्टॉल को प्रभाग समिति से मिलेगी अनुमति

मनपा ने जारी किए दिशा-निर्देश

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। रमजान पर्व को ध्यान में रखते हुए भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका ने शहर के व्यापारियों और नागरिकों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मनपा प्रशासन के अनुसार 19 फरवरी से 21 मार्च 2026 तक रमजान अवधि के दौरान अस्थायी स्टॉल लगाने की अनुमति संबंधित प्रभाग समिति कार्यालयों के माध्यम से दी जाएगी।

मनपा आयुक्त के निर्देशानुसार जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि रमजान के दौरान शहर में स्वच्छता और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई नियम लागू किए गए हैं। इफ्तार के बाद होने वाले कचरे की उचित तरीके से सफाई, अतिरिक्त कचरा डिब्बों की व्यवस्था, नियमित झाड़ू और डीप क्लीनिंग सुनिश्चित करने के लिए होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दिन में दो बार कचरा डिब्बों की सफाई अनिवार्य होगी। मनपा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रमजान ईद के लिए लगाए जाने वाले अस्थायी स्टॉल केवल महानगरपालिका द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही लगाए जा सकेंगे। प्रत्येक स्टॉल में अग्निशमन से जुड़े आवश्यक सुरक्षा उपाय करना अनिवार्य रहेगा। स्टॉल संचालकों को अपने स्तर पर कचरा डिब्बा रखना होगा और स्टॉल के सामने कचरा न फैले इसकी जिम्मेदारी भी उनकी होगी। प्लास्टिक बैग के उपयोग से बचने की अपील भी की गई है।यातायात विभाग को निर्देश दिया गया है कि रमजान के दौरान कहीं भी ट्रैफिक बाधित न हो। नागरिकों को दिखाई देने वाली जगह पर 'धूम्रपान निषेध' बोर्ड लगाना भी आवश्यक रहेगा। मनपा प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन या स्थान को लेकर विवाद होने पर अस्थायी स्टॉल की अनुमति तत्काल रद्द की जा सकती है।महानगरपालिका की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि रमजान पर्व शांतिपूर्ण, स्वच्छ और अनुशासित तरीके से मनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करें।

टेंपो सवार महिला से 10 हजार रुपये झपटे

थरवई (प्रयागराज)। थाना क्षेत्र के बसमहुआ गांव के समीप गुरुवार दोपहर बाइक सवार दो बदमाशों ने टेंपो में बैठी महिला का पर्स झपटकर फरार हो गए। पर्स में 10 हजार रुपये नकद रखे थे।मलाका मय भैसाही गांव निवासी प्रमिला पटेल (35) पत्नी कृष्ण कुमार पटेल सहसो बाजार कपड़ा खरीदने जा रही थीं।पीड़िता ने थरवई थाने में तहरीर दी है। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

मजबूत संख्या होने के बावजूद भाजपा के समर्थन के आरोप, राहुल गांधी से हस्तक्षेप की मांग

महापौर चुनाव से पहले कांग्रेस में सियासी विस्फोट, 'पार्टी बेचने' के आरोपों? से मचा हड़कंप

प्रदेश नेतृत्व और सपा विधायक पर भाजपा को लाभ पहुंचाने के आरोप; व्हिप जारी होने के बाद स्थानीय नेताओं में असंतोष बढ़ा।

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका के महापौर चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया है। भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक एडवोकेट अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक तीखा और गंभीर आरोपों से भरा पत्र भेजकर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पत्र में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल और भिवंडी पूर्व के समाजवादी पार्टी विधायक रईस शेख पर पार्टी को भाजपा के पक्ष में झुकाने का आरोप लगाया गया है। पत्र में दावा किया गया है कि प्रदेश नेतृत्व ने समाजवादी पार्टी के विधायक के साथ मिलकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के कुल 42 नगरसेवकों को भाजपा उम्मीदवार नारायण रतन चौधरी के समर्थन में खड़ा कर दिया है। मोमिन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत जाकर 18 फरवरी 2026 को आधिकारिक व्हिप जारी किया गया और नगरसेवकों पर भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

90 सदस्यीय महानगरपालिका सदन में कांग्रेस के पास 30 और एनसीपी के पास 12 सीटें होने के कारण सेक्युलर गठबंधन को मजबूत स्थिति में बताया जा रहा था। इसके बावजूद कांग्रेस के हिस्से में आने वाला महापौर पद भाजपा को सौंपने की साजिश रचे जाने का आरोप पत्र में लगाया गया है। मोमिन ने कहा कि उन्होंने पांच निर्दलीय पार्षदों के समर्थन के साथ कांग्रेस का महापौर बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे प्रदेश नेतृत्व ने अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही उपमहापौर पद के लिए एक अनुभवहीन व्यक्ति और सपा विधायक रईस शेख के निजी सहायक तारिक मोमिन को आगे बढ़ाने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि व्हिप जारी कर असहमत नगरसेवकों पर दबाव बनाया जा रहा है।

भिवंडी को अल्पसंख्यक बहुल शहर माना जाता है और यहां 48 पार्षद इसी समुदाय से जुड़े बताए जाते हैं। पत्र में चेतावनी दी गई है कि कथित 'अपवित्र गठबंधन' से स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है। सोशल मीडिया पर भी यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष दल भाजपा और आरएसएस से जुड़े राजनीतिक समीकरणों का समर्थन क्यों कर रहे हैं। महापौर चुनाव 20 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजे प्रस्तावित है। वहीं, 21 फरवरी को राहुल गांधी के भिवंडी दौरे और आरएसएस से जुड़े एक कोर्ट केस में उनकी उपस्थिति से पहले यह विवाद और ज्यादा राजनीतिक महत्व हासिल कर चुका है। स्थानीय नागरिकों और मीडिया द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। मोमिन ने राहुल गांधी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में नया व्हिप जारी करने और एनसीपी (एसपी) के समर्थन से पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की अपील की है। महापौर चुनाव से पहले सामने आए इन आरोपों ने भिवंडी की राजनीति को हाई-वोल्टेज बना दिया है और अब सभी की नजरें पार्टी नेतृत्व की अगली रणनीति पर टिकी हैं।

सुप्रिया सुले बोलीं- Ajit Dada की मौत से परिवार दुखी, Plane Crash पर शक गहराया

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने गुरुवार को एक दुखद विमान दुर्घटना में अपने पिता अजीत पवार के अचानक निधन पर पार्थ पवार और जय पवार के शोक को व्यक्त किया। सुले ने पत्रकारों से कहा कि अजित दादा की मृत्यु से पार्थ और जय बहुत दुखी हैं। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि विमान दुर्घटना कैसे हुई। जय ने भी कल इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए। अजित पवार और चार अन्य लोगों की 28 जनवरी की सुबह पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश के दौरान विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

इस बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक ज्ञापन सौंपकर बारामती विमान दुर्घटना में पूर्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजित पवार की मृत्यु की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग की। दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद प्रफुल पटेल, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ और युवा नेता पार्थ पवार ने ज्ञापन सौंपा।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एससीपी), शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस ने इस घटना पर सवाल उठाते हुए इसमें साजिश की आशंका जताई है। इससे पहले, सुप्रिया सुले ने अजित पवार की मृत्यु में साजिश की आशंका जताए जाने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय से स्पष्टीकरण की उम्मीद है। सुले ने कहा कि अजित पवार, रोहित पवार के चाचा थे। रोहित पवार समेत कई अन्य लोगों को इस मामले में चिंता और बेचैनी है। अमोल मितकारी ने भी सवाल उठाए हैं। शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस ने हमारा पूरा समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए और इस संबंध में उन्होंने अध्यक्ष से मुलाकात भी की।

कई घायल, दो अलग-अलग मामलों में केस दर्ज

बच्चों के विवाद से भड़की हिंसा, लाठी-डंडों से हमला

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

- अल्फा कॉम्प्लेक्स इलाके में मारपीट से दहशत
- परिजनों पर हमला और घर में तोड़फोड़ का आरोप,आरोपी फरार

भिवंडी। शहर के भोईवाडा पुलिस थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट और हमले में बदल गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत लेकर चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार भंडारी कंपाउड स्थित अल्फा कॉम्प्लेक्स निवासी मोहम्मद अहमद अफजल अंसारी (22) ने आरोप लगाया कि 18 फरवरी की शाम करीब 5:30 बजे उनके बेटे और पड़ोस के बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर शाकिर रियाज अहमद शेख और उसके रिश्तेदार मोहम्मद तारिक इसराइल खान मौके पर पहुंचे। दोनों ने गाली-गलौज करते हुए शिकायतकर्ता के पिता को पकड़ लिया और लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

वहीं दूसरे पक्षकार मोहम्मद शाकिर रियाज अहमद शेख (45) ने आरोप लगाया कि बच्चों के विवाद के बाद पूछताछ करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। इस दौरान लाठी-डंडों से हमला किया गया और घर के बाहर तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया। घटना में शिकायतकर्ता और उनकी मां घायल हो गईं। भोईवाडा पुलिस ने परस्पर एक दूसरे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भिवंडी में नशे का बड़ा खेल बेनकाब, कोडीन सिरप की 123 बोतलें जब्त

पुलिस को देख बीच सड़क पर फेंककर फरार हुआ आरोपी, NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। शहर में नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए शांतीनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर कोडीन युक्त कफ सिरप की भारी खेप बरामद की है। अशोकनगर स्थित पोस्ट ऑफिस के सामने संदिग्ध गतिविधि के आधार पर पुलिस ने एक युवक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नशीली दवाइयों से भरी बोतलें बीच सड़क पर फेंककर मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार 15 फरवरी की सुबह करीब 9:45 बजे एक संदिग्ध युवक बाइक पर जाता दिखाई दिया। शक होने पर पुलिस टीम ने उसे रोककर जांच की, जिसमें उसकी मोटरसाइकिल से Triprolidine Hydrochloride और Codeine Phosphate युक्त TUSKLIS-T सिरप की कुल 123 बोतलें बरामद हुईं। जब्त माल की कीमत करीब 1 लाख 40 हजार 530 रुपये बताई जा रही है। आरोपी की पहचान भिवंडी निवासी जाफर मकानदार के रूप में हुई है। पुलिस कार्रवाई के दौरान वह मौके से फरार हो गया। पुलिस शिपाई निलेश भास्कर पाटील की शिकायत पर NDPS एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सहायक पुलिस निरीक्षक योगेश गायकर मामले की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी यह नशीला सामान कहां से लाया और किसे सप्लाई करने जा रहा था।

Shivneri Fort से सुनेत्रा पवार का पहला भाषण, बोलीं- Ajit Pawar बार-बार महाराज को नमन करते थे

मुंबई। महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने गुरुवार को पुणे के शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने पहले सार्वजनिक भाषण में पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को याद किया।

इस अवसर पर बोलते हुए, उपमुख्यमंत्री ने खुशी व्यक्त की और कहा कि यह दिन आत्मसम्मान, स्वराज और सुशासन के प्रति संकल्प को मजबूत करने का दिन है। उन्होंने कहा, हाल ही में मैंने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मैंने यह शपथ एक चुनौतीपूर्ण समय में ली, और उस समय मेरी आंखों के सामने जीजामाता थीं। जीजामाता ने न केवल शिवाजी महाराज को जन्म दिया, बल्कि उन्हें स्वराज की स्थापना और संकटों का साहसपूर्वक सामना करना भी सिखाया। यही वह प्रेरणा है जो हम दोनों का मार्गदर्शन करती है, और यही हमारी नींव भी है।

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पूर्व उपमुख्यमंत्री और अपने पति, स्वर्गीय अजीत पवार को याद करते हुए कहा कि वे छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, ज्योतिराव गोविंदराव फुले और बी.आर. अंबेडकर के आदर्शों पर चले। अपने पूरे जीवन में अजीत पवार शिव, शाहू, फुले और अंबेडकर के आदर्शों पर चलते रहे। मैं आज इस पवित्र भूमि से आपको आश्वस्त करती हूं कि मैं इस विचारधारा के विचारों की विरासत को कभी नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने आगे कहा कि अजीत पवार शिवनेरी किले को केवल एक ऐतिहासिक स्थल ही नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी मानते थे। मुझे याद आता है कि इसी स्थान से अजीत पवार ने बार-बार शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की और जनता को स्वराज का संदेश दिया... जनता के साथ उनका स्नेह का बंधन अत्यंत मजबूत और अटूट था।

उन्होंने कहा कि पवार ने इस स्थल की सुंदरता को बनाए रखने और सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, और इस बात पर जोर दिया कि शिवनेरी किले को 2025 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था।

छत्रपति शिवाजी महाराज 17वीं शताब्दी के भारतीय योद्धा राजा थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्हें भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को मनाई जाती है।

Technical Glitch से एयरपोर्ट पर हड़कंप, Delhi-Mumbai में सुबह-सुबह फंसे हजारों यात्री

नई दिल्ली।दिल्ली और मुंबई समेत कई हवाई अड्डों पर सैकड़ों यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा, जब एयरलाइंस द्वारा बुकिंग और चेक-इन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली नेविटेयर में 45 मिनट की तकनीकी खराबी आ गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह खराबी सुबह करीब 6:45 बजे सामने आई। व्यवधान के दौरान, एयरलाइंस को यात्रियों की जानकारी मैन्युअल रूप से प्रबंधित करनी पड़ी, जिससे सुबह की भीड़भाड़ के समय लंबी कतारें लग गईं। इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस समेत कई एयरलाइंस प्रभावित हुईं। सूत्रों ने बताया कि इंडिगो ने लगभग 25 मिनट में अपने सिस्टम को बहाल कर लिया। सूत्रों के अनुसार, नेविटेयर का सिस्टम लगभग दो घंटे बाद सुबह 8:25 बजे तक पूरी तरह से बहाल हो गया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली, जहां नेविटेयर सिस्टम में खराबी के कारण कई यात्रियों ने चेक-इन काउंटरों पर देरी और भीड़भाड़ की शिकायत की। नेविटेयर एयरलाइन आरक्षण, चेक-इन और बोर्डिंग के लिए महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान करती है। जब यह सिस्टम विफल हो जाता है, तो एयरलाइनें यात्रियों को कुशलतापूर्वक सेवा देने में असमर्थ हो जाती हैं, जिससे अक्सर देरी और भीड़भाड़ हो जाती है। इस घटना ने पिछले साल नवंबर में हुई एक बड़ी व्यवधान की यादें ताजा कर दीं, जब दिल्ली हवाई अड्डे पर वायु यातायात नियंत्रण प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण 800 से अधिक उड़ानें विलंबित हो गई थीं।

Climate Change पर मंत्री Shivraj Singh की चेतावनी, बोले- सरकार के साथ समाज भी उठाए धरती बचाने की जिम्मेदारी

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को जलवायु परिवर्तन को विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठा रही है, लेकिन इस धरती को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जनता की भी है। मीडिया से बात करते हुए चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज विश्व के सामने सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। विश्व के कई देशों ने पहले ही यह संकल्प लिया है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए कदम उठाने होंगे। सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर देश के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

मंत्री ने आगे इस बात पर जोर दिया कि भावी पीढ़ियों की सुरक्षा की

जिम्मेदारी सरकार और समाज दोनों की है, और कहा, 'यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है - भावी पीढ़ियों के लिए इस धरती को सुरक्षित रखना समाज का भी कर्तव्य है।' इस बीच, भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जलवायु कार्रवाई पर खर्च छह साल पहले सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.7 प्रतिशत से बढ़कर आज लगभग 5.6 प्रतिशत हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 फरवरी को जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित 'अस्थिरता की डिग्रीः गर्म होती दुनिया में जलवायु सुरक्षा' टाउनहॉल में बोलते हुए ये आंकड़े साझा किए।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत केवल अंतरराष्ट्रीय सहायता की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से अपने संसाधनों का निवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कई पहलें भी शुरू की हैं, जैसे मिशन मौसम, मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम और अमृत सरोवर। 14 जनवरी को उन्होंने पोंगल से संबंधित एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की रक्षा करना 'सर्वोच्च आवश्यकताओं' में से एक है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मिट्टी की रक्षा करना, जल संरक्षण करना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम और अमृत सरोवर जैसी पहलें इसी भावना को आगे बढ़ा रही हैं।

मनोरंजन

केजीएफ स्टार यश की पत्नी राधिका पंडित ने किया दिल छू लेने वाला पोस्ट; कैप्शन में लिखे प्यार और आभार भरे जज़्बात!

मुंबईः राधिका पंडित ने अपने पति, रॉकिंग स्टार यश के लिए एक बेहद निजी और भावुक संदेश साझा किया, जिसने देखते ही देखते सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच लिया। पानी के किनारे आतिशबाज़ी निहारते हुए अपनी और यश की एक रोमांटिक तस्वीर साझा करते हुए राधिका ने अपने कैप्शन में प्यार और आभार से भरे जज़्बात लिखे। उन्होंने उन खामोश कुर्बानियों और अथक मेहनत का ज़िक्र किया, जो यश अपने परिवार के लिए करते हैं। राधिका पंडित ने लिखा, 'उस शख्स के नाम, जिसने मुझे ऐसे नाचने का हौसला दिया जैसे कोई देख ही नहीं रहाष्ठ मैं तुम्हारी आंखों की थकान देखती हूं, वो बलिदान जो किसी और को नज़र नहीं आते, लंबे दिनों का बोझ जिसे तुम बिना शिकायत उठाते होष्ठ मुझे पता है ये सब हमारे लिए है। हर एक दिन मुझे चुनने के लिए शुक्रिया। हैप्पी वैलेंटाइन डे, मेरे हमेशा के लिए ।'

यह सादगी भरा लेकिन दिल छू लेने वाला पोस्ट फैंस के दिलों में उतर गया। लोगों ने इस जोड़ी की मज़बूत समझ, आपसी सम्मान और लंबे साथ की जमकर तारीफ की। अपनी निजी जिंदगी को हमेशा गरिमा और सादगी के साथ संभालने वाले इस कपल की तरफ से यह एक दुर्लभ झलक थी, जिसने उनके रिश्ते की गहराई दिखा दी।जहां एक तरफ यश अपने व्यस्त प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को संभाल रहे हैं, वहीं राधिका का यह प्यार भरा संदेश याद दिलाता है कि हर चमकते सितारे के पीछे अडिग साथ और भरोसे की ताकत होती है।कैमरे के सामने भी और कैमरे के पीछे भी।

मुक्ता आर्ट्स और ग्रीन गोल्ड एनीमेशन मिलकर बनाएंगे प्रतिष्ठित फिल्मों पर एनिमेटेड दुनिया!

मुंबईः प्रख्यात फिल्ममकार सुभाष घई की कंपनी मुक्ता आर्ट्स और ग्रीन गोल्ड एनिमेशन ने मुक्ता आर्ट्स की प्रतिष्ठित बौद्धिक संपदा (आईपी) पर आधारित एनिमेटेड शो और फीचर फिल्मों के विकास एवं निर्माण के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। एनिमेशन क्षेत्र में अपनी रणनीतिक विस्तार योजना के तहत मुक्ता आर्ट्स ने 2025 में एसजीएम एनीमेशन स्टूडियो लॉन्च किया, जो कंपनी का समर्पित एनिमेशन और गेम्स डिवीजन है। यह स्टूडियो एनिमेटेड फिल्में, सीरीज, कॉमिक बुक्स और गेम्स के विकास, निर्माण और सह-निर्माण पर केंद्रित है।

साथ ही यह चार दशकों में बने मुक्ता आर्ट्स के समृद्ध आईपी लाइब्रेरी का उपयोग करते हुए नई ओरिजिनल प्रॉपर्टीज भी तैयार करेगा, जो कंपनी की कहानी कहने की विरासत से प्रेरित होंगी। इस एमओयू के तहत मुक्ता आर्ट्स और ग्रीन गोल्ड एनिमेशन मिलकर मुक्ता आर्ट्स की प्रतिष्ठित फिल्मों से प्रेरित कई एनिमेटेड आईपी विकसित करेंगे।

इनमें प्रमुख रूप से कालीचरण, क़र्ज़, हीरो, कर्मा, राम लखन, खलनायक, सौदागर, इक़बाल सहित कई अन्य फिल्मों के साथ इनके किरदारों पर आधारित स्पिन-ऑफ भी शामिल होंगे।

मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड के संस्थापक और निर्माता सुभाष घई ने कहा, 'मुक्ता आर्ट्स हमेशा से भावनात्मक रूप से जुड़ी कहानियां बनाने में विश्वास रखता है। एनिमेशन के माध्यम से हम अपनी आईपी को अगली पीढ़ी के लिए एक नए माध्यम में विस्तार दे रहे हैं।' इस सहयोग पर बात करते हुए ग्रीन गोल्ड एनिमेशन के संस्थापक और सीईओ राजीव चिलाका ने कहा, 'एसजीएम स्टूडियो के साथ यह साझेदारी हमें लंबे समय तक चलने वाले एनिमेशन आईपी बनाने के अपने अनुभव को एक प्रतिष्ठित फिल्म कैटलॉग पर लागू करने का अवसर देती है।

साथ मिलकर हम ऐसी एनिमेटेड दुनिया बनाना चाहते हैं जो इन महान कहानियों से जुड़ी हो और आज के युवा वैश्विक दर्शकों से भी जुड़ सके।' यह साझेदारी भारतीय सिनेमा की प्रतिष्ठित विरासत को नई तकनीक और नए फॉर्मेट के जरिए वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

विन डीजल ने 'द ब्लफ' के लॉस एंजेलिस प्रीमियर में प्रियंका चोपड़ा की प्रशंसा की!

लॉस एंजेलिस। हॉलीवुड सितारे विन डीजल ने एक्शन थ्रिलर फिल्म 'द ब्लफ' के लॉस एंजेलिस प्रीमियर में शिरकत की और प्रियंका चोपड़ा के अभिनय और पर्दे के साथ-साथ निजी जीवन में उनके व्यक्तित्व की जमकर सराहना की। यह कार्यक्रम टीसीएल चाइनीज थिएटर में आयोजित किया गया, जहां इसने फिल्म और दोनों सितारों के बीच मधुर संवाद के कारण फिल्म जगत के जानकारों और जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा।

प्रीमियर के दौरान डीजल ने प्रेस से बात करते हुए प्रियंका के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने प्रियंका को एक उत्कृष्ट कलाकार और एक ऐसा व्यक्ति बताया जिसने उनके परिवार पर स्थायी छाप छोड़ी है। अपनी पिछली मुलाकातों को याद करते हुए, उन्होंने प्रियंका को अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली बताया और साझा किया कि एक फिल्म के यूरोपीय प्रदर्शन के दौरान प्रियंका ने उनके बच्चों के साथ कितनी गर्मजोशी से बातचीत की थी।

कार्यक्रम के एक वीडियो में डीजल उनके बीच के अनूठे संबंध पर प्रकाश डालते यह बताते नजर आये कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है। उन्होंने कहा, 'सबसे पहले, मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताने जा रहा हूं। वह इस फिल्म में बहुत अद्भुत हैं, वह एक अविश्वसनीय प्रतिभा हैं और यूरोप में जब फिल्म का प्रदर्शन हुआ था, तब वह मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आई थीं। हमारा जन्मदिन एक ही दिन होता है, और मैं चाहता हूं कि आप जिस अन्य व्यक्ति के बारे में सोचें, वह दिवंगत नेल्सन मंडेला हैं। इसलिए वह, नेल्सन मंडेला और मैं, हम सभी इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।'

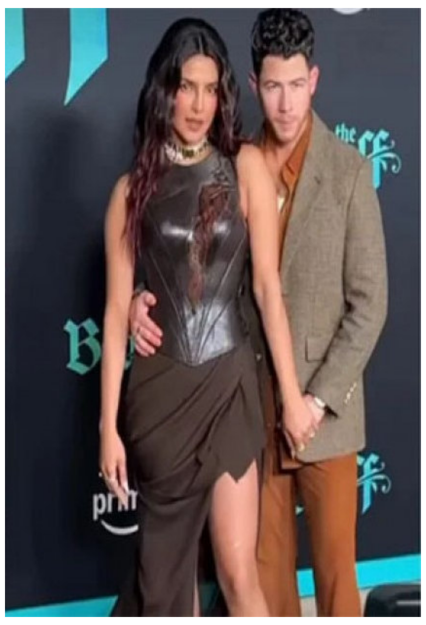

प्रीमियर में प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनास के साथ दिखाई दीं। उनके साथ फिल्म के कलाकार कार्ल अर्बन, सफिया ओकले-ग्रीन, वेदांतेन नायडू और तेमुएरा मॉरिसन भी मौजूद थे। निर्देशक फ्रैंक ई. फ्लावर्स और निर्माता एंथनी रूसो भी उनके साथ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हुए। विन डीजल अपनी बेटी हनिया राइली सिंक्लेयर के साथ पहुंचे थे और अभिनेत्री शेरोन स्टोन भी वहां उपस्थित थीं। फिल्म के निर्देशक फ्रैंक ई. फ्लावर्स हैं और जो बलारिनी इसके सह-लेखक हैं। 'द ब्लफ' 19वीं सदी के उत्तरार्ध के कैरिबियन इलाके की कहानी है। प्रियंका इसमें 'एर्सेल ब्लडी मैरी बोडेन' की भूमिका निभा रही हैं, जो एक पूर्व समुद्री डाकू है और अपने परिवार के साथ शांति की तलाश में है। उसका अतीत तब फिर से सामने आ जाता है जब कैप्टन कॉनर (कार्ल अर्बन अभिनीत पात्र) के नेतृत्व में उसका पुराना दल उसका पीछा करता है। यह फिल्म प्रायश्चित और सुरक्षा के विषयों के बीच घूमती है। इसमें प्रियंका अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए पुराने विरोधियों के खिलाफ खड़ी होती है। 'द ब्लफ' 25 फरवरी को 'प्राइम वीडियो' पर प्रदर्शित होने वाली है।

अजेय रहते हुए सुपर-8 में पहुंचा जिम्बाब्वे, श्रीलंका को उसके घर में छह विकेट से दी करारी शिकस्त

कोलंबो। ब्रायन बेनेट की तूफानी अर्धशतकीय पारी की मदद से जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को छह विकेट से करारी शिकस्त दी। इसी के साथ सिकंदर रजा की अगुवाई वाली टीम ने टी20 विश्व कप 2026 में ग्रुप स्टेज का अजेय रहते हुए समापन किया और सुपर-8 में शानदार एंट्री की। गुरुवार को कोलंबो में खेले गए 38वें मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट पर 178 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे ने तीन गेंदों के शेष रहते 182 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया।

ग्रुप-बी की टेबल टॉपर बनी जिम्बाब्वे

इस जीत के साथ जिम्बाब्वे की टीम ने ग्रुप बी की टेबल टॉपर भी बन गई। लीग चरण में खेले चार मुकाबलों में उसने तीन मैचों में शानदार जीत दर्ज की। वहीं, एक मैच बेनतीजा रहा। टीम सात अंक और ₹ 1.506 के नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर पहुंच गई। इस हार के साथ मेजबान श्रीलंका दूसरे स्थान पर खिसक गई। उसके खाते में छह अंक और ₹1.741 का नेट रन रेट है। ग्रुप बी से सुपर-8 के लिए जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। वहीं, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ओमान का सफर ग्रुप स्टेज में ही समाप्त हो गया है। इस ग्रुप का आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच खेला जाना है।

जिम्बाब्वे ने किया एक और उलटफेर

जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर टी20 विश्व कप 2026 में एक बार फिर बड़ा उलटफेर कर दिया। इससे पहले टीम ने ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया था। जिम्बाब्वे की टीम सुपर-8 में भारत, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के साथ ग्रुप-1 में है, जबकि श्रीलंकाई टीम न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान के साथ ग्रुप-2 में है।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम को कुसल परेरा और पथुम निसांका की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने पांच ओवरों में 54 रन की साझेदारी की। कुसल 14 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद निसांका ने कुसल मेंडिस के साथ 43 गेंदों में 46 रन जुटाते हुए श्रीलंका को 100 के स्कोर तक पहुंचाया। मेंडिस ने टीम के खाते में 14 रन का योगदान दिया, जबकि निसांका ने 41 गेंदों में 8 चौकों के साथ 62 रन टीम के खाते में जोड़े। इनके अलावा, पवन रत्नायके ने 25 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 44 रन की पारी खेली। विपक्षी खेमे से ब्लेसिंग मुजारबानी, ब्रैड इवांस और ग्रीम क्रेमर ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि एक विकेट रयान बर्ल के हाथ लगा।

जिम्बाब्वे की पारी

जवाब में जिम्बाब्वे ने 19.3 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। इस टीम को ब्रायन बेनेट और तदिवानाशे मारुमानी की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों के बीच 8.3 ओवरों में 69 रन की साझेदारी हुई। मारुमानी 26 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 34 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बेनेट ने रयान बर्ल के साथ दूसरे विकेट के लिए 29 रन जुटाते हुए टीम को 98 के स्कोर तक पहुंचाया। बर्ल 12 गेंदों में 3 बाउंड्री के साथ 23 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। यहां से बेनेट ने कप्तान सिकंदर रजा के साथ 40 गेंदों में 69 रन जुटाते हुए टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। सिकंदर रजा 26 गेंदों में 4 छक्कों और 2 चौकों के साथ 45 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बेनेट ने 48 गेंदों में 8 चौकों के साथ 63 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को शानदार जीत दिलाई। मेजबान खेमे की तरफ से दुशन हेमंथा ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए, जबकि दसुन शनाका और दुनिथ वेल्लालगे ने 1-1 विकेट हासिल किया।

सेपक टाकरा प्रतियोगिता के लिए रुहेलखंड विश्वविद्यालय की टीम का चयन, इन खिलाड़ियों को मिली जगह

बरेली। बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतर-महाविद्यालयीय सेपक टाकरा (महिला/पुरुष) प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय से संबद्ध चार महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।

प्रतियोगिता के आधार पर असम विश्वविद्यालय में होने वाली अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालयीय सेपक टाकरा (महिला/पुरुष) प्रतियोगिता के लिए श्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ी अंतर-विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में रुहेलखंड विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे।

इन खिलाड़ियों का टीम में हुआ चयन

पुरुष टीम में विनय यादव, जतिन, उवेश, अमन, आर्यन, अमित, आश्मित, सार्थी, युवराज, सतीश, शानू, पृथ्वी, अभय, अनमोल व योगेश को शामिल किया गया। वहीं, महिला वर्ग में राशिका, सुहानी, समरीन, मोहिनी, चंचल, तान्या यादव, वंशिका, नंदिनी, नीलम, शालिनी राय, दिव्यांका पांडेय, यंत्रा व जिया का टीम में चयन हुआ।

प्रतियोगिता के दौरान क्रीड़ा सचिव प्रो. एसएस बेदी, परीक्षा नियंत्रक संजीव कुमार सिंह, क्रीड़ा सचिव परिसर डॉ. नीरज कुमार, सह-क्रीड़ा सचिव डॉ. अजीत सिंह, विजय कुमार सिंहाल, डॉ. इंद्रप्रीत कौर, डॉ. इरम नईम आदि उपस्थित रहे। टीम का चयन लकी, शुभम तिवारी की ओर से किया गया। ऑफिशियल की भूमिका दीपक मौर्य ने निभाई।

शहबाज सरकार की पोल खोलना पड़ा हॉकी टीम के कप्तान को भारी, दो साल का प्रतिबंध; संघ अध्यक्ष का इस्तीफा

कराची। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद शकील बट को शहबाज सरकार की पोल खोलना भारी पड़ा है। उन पर दो साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध पाकिस्तान हॉकी संघ (पीएचएफ) के अध्यक्ष तारिक बुगती ने अम्माद पर लगाया। वहीं, इस कार्रवाई के बाद बुगती ने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया। दरअसल, बुधवार को पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान ने हालिया ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटने के बाद राष्ट्रीय महासंघ की जमकर आलोचना की थी। उन्होंने कहा, इस दौरे के दौरान उनकी टीम को न केवल होटल में बुकिंग नहीं होने के कारण सड़कों पर भटकना पड़ा, बल्कि मैच खेलने के लिए जाने से पहले बर्तन भी धोने पड़े।

कप्तान अम्माद को मिली सच बोलने की सजा?

बुगती ने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा संघ के मुख्य संरक्षक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भेज दिया है। उन्होंने कहा, 'मैंने अपना इस्तीफा पीएम को भेज दिया है, लेकिन मैं उनसे और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुजारिश करता हूं कि वे एफआईएच प्रो लीग हॉकी के दौरान ऑस्ट्रेलिया में हुई पूरी स्थिति की निष्पक्ष जांच करें।' इस दौरान बुगती ने कप्तान अम्माद शकील बट पर लगाए गए प्रतिबंध का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अम्माद को दो साल के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हॉकी से दो साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

कप्तान बट ने किया बगावत का एलान

अम्माद शकील बट ने बुधवार को बगावत का एलान करते हुए कहा था, 'हम महासंघ के मौजूदा प्रबंधन के रहते हुए खेलना जारी नहीं रख सकते। जब खिलाड़ियों को मैच खेलने जाने से पहले रसोई साफ करनी पड़ती है और बर्तन धोने पड़ते हैं तो आप हमसे कैसे अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं।' सरकारी स्वामित्व वाले पाकिस्तान खेल बोर्ड (पीएसबी) ने यह पुष्टि की थी कि उसने ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय टीम के होटल में ठहरने की व्यवस्था के लिए पीएचएफ को एक करोड़ से अधिक पाकिस्तानी रुपये दिए थे। इसके बाद पीएचएफ को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा।

हवाई अड्डे पर करना पड़ा इंतजार

पाकिस्तान हॉकी टीम को कैनबरा जाने वाली अपनी अगली उड़ान से पहले सिडनी हवाई अड्डे पर 13-14 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इससे भी अधिक चिंताजनक खबरें तब सामने आईं जब टीम एफआईएच प्रो लीग मैचों से पहले अपने होटल में पहुंची थी। खिलाड़ियों को बताया गया कि उनकी कोई बुकिंग नहीं है क्योंकि होटल को किसी तरह का अग्रिम भुगतान नहीं किया गया था। बट ने यह भी आरोप लगाया कि ज्यादातर खिलाड़ियों को पिछले एक साल से पीएसबी और पीएचएफ से उनके डेली अलाउंस नहीं मिले हैं।

पीएसबी और पीएचएफ में छिड़ी जंग

इस मामले में पाकिस्तान खेल बोर्ड और पीएचएफ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बुगती ने पीएसबी को कसूरवार ठहराते हुए कहा कि आस्ट्रेलिया दौरे पर सारे इंतजाम उसी ने किए थे।

ऐसा हुआ तो टी20 विश्वकप में फिर होगा महामुकाबला! भारत-पाकिस्तान आ सकते हैं आमने-सामने, पूरा समीकरण

नई दिल्ली। टी20 विश्वकप 2026 का रोमांच फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। अब तक इस विश्वकप में कई दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले हैं। 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप स्टेज से बाहर होना चौंकाने वाला रहा। वहीं, जिम्बाब्वे ने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया। कई एसोसिएट टीमें भले ही सुपर-आठ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाईं हों, लेकिन उनक कई खिलाड़ियों ने बल्ले और गेंद से सुर्खियां बटोरीं। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले कई विवाद हुए, लेकिन यह विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच होने के साथ ही शांत हो गया।

भारत ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी

टीम इंडिया ने ग्रुप-ए के मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 61 रन से करारी शिकस्त दी और पड़ोसियों और उनके फैंस का मुंह बंद कर दिया। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का एलान किया था और तब वहां के क्रिकेट पंडित और फैंस फर्जी बयानबाजी करते दिखे थे। फिर आईसीसी के चाबुक के डर से टूर्नामेंट शुरू होते-होते पाकिस्तान ने यू-टर्न ले लिया और टीम इंडिया के खिलाफ खेलने को तैयार हो गए।

ग्रुप स्टेज में भारत शीर्ष पर, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर

भारतीय टीम ने ग्रुप-ए में अपने सभी मैच जीते और अंक तालिका में शीर्ष पर रही। वहीं, पाकिस्तान की टीम चार में से तीन मैच जीतकर ग्रुप-ए में दूसरे स्थान पर रही। उसे सुपर-आठ में पहुंचने के लिए जूझना पड़ा और नामीबिया के खिलाफ आखिरी मैच को जीतकर सुपर-आठ के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रही। 2009 की टी20 चैंपियन पाकिस्तान टीम में कई खामियां देखने को मिलीं और नीदरलैंड्स अगर उन्हें पहले मुकाबले में हरा देता तो टीम बाहर भी हो सकती थी। पाकिस्तान नीदरलैंड्स के खिलाफ ग्रुप-ए मुकाबला तीन गेंद शेष रहते जीता था।

क्या फिर से हो सकता है भारत-पाकिस्तान मुकाबला?

इस टूर्नामेंट में 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। सभी टीमों को पांच-पांच टीमों के चार ग्रुप्स में बांटा गया। हर ग्रुप से शीर्ष-दो टीमों ने सुपर आठ राउंड के लिए क्वालिफाई किया। अब सुपर-आठ राउंड में चार-चार टीमों के दो ग्रुप्स बने हैं और टीमें आईसीसी द्वारा पहले से ही तैयार की गई सीडिंग्स के अनुसार तय की गई हैं। सुपर आठ राउंड में भारत को ग्रुप-1 में जबकि पाकिस्तान को ग्रुप-2 में जगह मिली है। टीम इंडिया के ग्रुप में वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की टीमें हैं। वहीं, पाकिस्तान के ग्रुप में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें हैं।

सुपर आठ राउंड में प्रत्येक ग्रुप की एक टीम अपने ग्रुप में मौजूद तीन अन्य टीमों के खिलाफ एक-एक मैच खेलेगी। ऐसे में भारत और पाकिस्तान की टीमें दो अलग-अलग ग्रुप में होने के कारण एक-दूसरे से तो नहीं भिड़ेंगी। सुपर-आठ में दोनों ग्रुप्स से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी।

गर्लफ्रेंड माहिका के जन्मदिन पर रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, खास अंदाज में दी बधाई

नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने गुरुवार को गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को उनके 25वें जन्मदिन पर खास अंदाज में बधाई दी। दोनों ने पिछले साल अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। बता दें कि, हार्दिक इन दिनों टी20 विश्व कप में खेलते नजर आ रहे हैं। भारत लगातार चार ग्रुप मैच जीतकर सुपर-8 में पहुंच चुका है।

हार्दिक ने किया माहिका को विश

हार्दिक पांड्या ने माहिक शर्मा को रोमांटिक अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने एक खास वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। इसमें दोनों बीच पर मस्ती करते दिख रहे हैं। हार्दिक ने कैप्शन में लिखा, जन्मदिन मुबारक हो मेरी प्रिंसेस। 25 साल पहले इस दुनिया में आने के लिए धन्यवाद। तुम सबसे अद्भुत इंसान हो जिसे मैं जानता हूं। आई लव यू!

रिलेशनशिप अब सार्वजनिक

हार्दिक और माहिका की नजदीकियां पहली बार अक्तूबर में मुंबई एयरपोर्ट पर देखी गई थीं। इसके बाद उनकी बीच वेकेशन की फोटोज सामने आईं और फिर हार्दिक ने माहिका के साथ फैमिली फंक्शन की तस्वीरें भी शेयर कीं। यह सब उनके 2024 में पत्नी नताशा स्टैनकोविक से शांतिपूर्ण अलगाव के बाद आया।

अक्तूबर 2025 में कंफर्म किया रिश्ता

पिछले साल अक्तूबर में, हार्दिक ने अपने और माहिका के बारे में अफवाहें सामने आने के बाद अपने रिश्ते को कन्फर्म किया था। उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर भी एक साथ देखा गया था। इस ऑलराउंडर ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर माहिका के साथ कई फोटो भी पोस्ट की थीं। वे एक साथ छुट्टियों पर भी गए थे।

कौन हैं माहिका शर्मा?

माहिका शर्मा एक मॉडल और अभिनेत्री हैं, जो अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर फैशन और फिटनेस कंटेंट भी बनाती हैं। लिंकडिन प्रोफाइल के मुताबिक, माहिका ने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के नेवी चिल्ड्रन स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने इकॉनोमिक्स और फाइनेंस की पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद माहिका ने कई जगह इंटर्नशिप भी की है।

पढ़ाई पूरी करने के बाद माहिका ने मॉडलिंग और एक्टिंग की ओर रुख किया। उन्होंने एक फ्रीलांसर के रूप में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद वो रैपर रागा के लिए एक म्यूजिक वीडियो में दिखाई दीं और बाद में फिल्मों में भी उन्होंने कई छोटी भूमिकाएं निभाईं। इनमें ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री निर्देशक ऑरलैंडो वॉन आइन्सिडेल की 'इनटू द डस्क' और ओमंग कुमार की 'पीएम नरेंद्र मोदी' (2019) भी शामिल है। इसमें वो विवेक ओबेरॉय के साथ नजर आई थीं। इसके अलावा वो कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में भी नजर आ चुकी हैं।

आईआरसीटीसी ने कसा शिकंजाः 3.03 करोड़ फर्जी प्रोफाइल अवरुद्ध, बुकिंग के लिए नए आधार से जुड़े नियम लागू

नई दिल्ली (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

वास्तविक यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान

बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए सरल एवं सहज उपयोगकर्ता अंतरफलक, दुरुपयोग रोकने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम, जो रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ने अपनी रेल टिकट बुकिंग वेबसाइट www.irctc.co.in तथा आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल अनुप्रयोग के उपयोगकर्ता अंतरफलक में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।

इन सुधारों का उद्देश्य लाखों रेल यात्रियों को तेज, सरल एवं अधिक सहज टिकट बुकिंग अनुभव प्रदान करना है। साथ ही, आईआरसीटीसी ने दुरुपयोग को रोकने, स्वचालित उपकरणों के माध्यम से की जाने वाली बुकिंग पर नियंत्रण स्थापित करने तथा तत्काल और अग्रिम आरक्षण अवधि टिकटों तक निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत एवं प्रशासनिक सुरक्षा उपायों को और अधिक सुदृढ़ किया है।

उपयोगकर्ता अंतरफलक सुधार - आईआरसीटीसी वेबसाइट (www.irctc.co.in)मुख्य सुधार इस प्रकार हैं :

बेहतर लोडिंग गति और अधिक प्रतिक्रिया क्षमता के साथ आकर्षक, स्वच्छ एवं सरल अंतरफलक

सहज मार्गदर्शन के लिए मेनू विकल्पों का पुनर्संरेखन

डेटा प्रविष्टि में सुविधा हेतु प्रपत्र क्षेत्रों का पुनर्विन्यास

त्वरित लॉगिन के लिए लॉगिन स्क्रीन से कैप्चा हटाया गया

ट्रेन सूची अब 'अवधि' के स्थान पर 'प्रस्थान समय' के अनुसार क्रमबद्ध

अनुकूलित दृश्य के लिए 'फ़िल्टर दिखाएं अथवा छिपाएं' सुविधा का प्रावधान

आधार सत्यापन के माध्यम से तत्काल एवं अग्रिम आरक्षण अवधि बुकिंग को सुदृढ़ करना

ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने तथा तत्काल टिकट बुकिंग में संभावित धोखाधड़ी पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय लागू किए गए हैं :

अग्रिम आरक्षण अवधि खुलने के दिन टिकट बुकिंग केवल आधार सत्यापित उपयोगकर्ताओं को ही अनुमत होगी।

तत्काल टिकट बुकिंग भी केवल आधार सत्यापित उपयोगकर्ताओं को ही करने की अनुमति होगी।

आधार आधारित सत्यापन की शुरुआत से अनधिकृत उपयोगकर्ता खातों के निर्माण एवं संचालन पर प्रभावी रोक लगी है। यह दुरुपयोग के विरुद्ध एक सशक्त सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य कर रहा है, जिससे अग्रिम आरक्षण अवधि खुलने के दिन तथा तत्काल

टिकटों का निष्पक्ष आवंटन सुनिश्चित किया जा सके। इससे पारदर्शिता बढ़ी है तथा अनुचित बुकिंग प्रथाओं में कमी आई है, परिणामस्वरूप वास्तविक यात्रियों के लिए टिकट उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

प्रणालीगत उपाय (सामग्री वितरण नेटवर्क एवं स्वचालित अवरोध तकनीक) टिकटिंग मंच की मजबूती और विश्वसनीयता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए :

स्थिर सामग्री को अलग सर्वरों पर उपलब्ध कराने और मुख्य सर्वर पर यातायात दबाव कम करने के लिए सामग्री वितरण नेटवर्क लागू किया गया है।

दुर्भावनापूर्ण एवं संदिग्ध स्वचालित प्रयासों को रोकने के लिए उन्नत स्वचालित अवरोध तकनीक तैनात की गई है।

इन उपायों से दुर्भावनापूर्ण यातायात को छानने, सर्वर प्रतिक्रिया समय सुधारने तथा वास्तविक एवं सत्यापित उपयोगकर्ताओं के लिए प्रणाली प्रदर्शन बेहतर बनाने में सहायता मिली है।

प्रशासनिक एवं धोखाधड़ी निरोधक उपाय आईआरसीटीसी ने अनधिकृत पहुंच को रोकने और वैध यात्रियों के लिए निर्बाध बुकिंग सुनिश्चित करने हेतु व्यापक धोखाधड़ी निरोधक तंत्र अपनाया है :

वर्ष 2025 में 3.03 करोड़ संदिग्ध उपयोगकर्ता पहचान निष्क्रिय की गईं। दुर्भावनापूर्ण यातायात की बड़ी मात्रा का नियमित अवरोधन किया गया।

3.99 लाख संदिग्ध पीएनआर से संबंधित 376 शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर दर्ज की गईं।

वर्ष 2025 में 4.86 करोड़ संदिग्ध उपयोगकर्ता पहचान पुनः सत्यापन के अधीन रखी गईं।

वर्ष 2025 में 12,819 संदिग्ध ईमेल डोमेन अवरुद्ध किए गए।

इन उपायों से ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

आईआरसीटीसी का नागरिक-प्रथम और पारदर्शी दृष्टिकोण, साइबर सुरक्षा उपायों का सुदृढ़ीकरण तथा आधार आधारित बुकिंग व्यवस्था मिलकर वास्तविक रेल यात्रियों के लिए तत्काल और अग्रिम आरक्षण अवधि टिकट बुकिंग को अधिक सरल और निष्पक्ष बना रहे हैं। फर्जी उपयोगकर्ता पहचान के उन्मूलन एवं स्वचालित अवरोध तकनीक के प्रभावी क्रियान्वयन से अब वास्तविक यात्रियों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है।

2027 में जिनेवा में होगा एआई समिट, स्विस राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन का एलान

नई दिल्ली। स्विस राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन ने गुरुवार को घोषणा की कि स्विट्ज़रलैंड वर्ष 2027 में जिनेवा में एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि इससे डिजिटल नीति के क्षेत्र में स्विट्ज़रलैंड की स्थिति मजबूत होगी और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि होगी।

भारत मंडपम में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन के दौरान स्विस पवेलियन में मीडिया से बातचीत करते हुए पार्मेलिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक को बेहतरीन बताया। दोनों नेताओं ने शिखर सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय वार्ता भी की।

जिनेवा में एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन पर क्या बोले स्विस राष्ट्रपति?

स्विस राष्ट्रपति ने कहा कि एआई केवल गति या अनुप्रयोग का विषय नहीं है, बल्कि इसका लोगों के जीवन पर सीधा और असाधारण प्रभाव पड़ता है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर भी कहा कि जिनेवा में 2027 का समिट जिम्मेदार एआई उपयोग, वैश्विक संवाद, शासन और नियमन को आगे बढ़ाने में योगदान देगा।

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा, 'नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एआई अभूतपूर्व गति से हमारे भविष्य को आकार दे रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सरकारें मिलकर काम करें, ज्ञान का आदान-प्रदान करें और यह सुनिश्चित करें कि एआई से सभी को लाभ मिले।'

'एआई का लाभ सभी को मिले' :गाइ पार्मेलिन

उन्होंने कहा कि सरकारों के बीच सहयोग, ज्ञान-साझाकरण और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि एआई का लाभ सभी को मिले। 16 से 20 फरवरी तक चल रहे इस समिट में कई राष्ट्राध्यक्षों, 500 से अधिक वैश्विक एआई नेताओं, 150 शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं तथा 400 से अधिक तकनीकी अधिकारियों और परोपकारियों की भागीदारी है।

गांधी परिवार ने मांगा और समय,ईडी की अपील पर अब 9 मार्च को सुनवाई।

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की नेशनल हेराल्ड मामले में दायर अपील पर सुनवाई के लिए 9 मार्च की तारीख तय कर दी। गांधी परिवार और अन्य पक्षों ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। शुरुआत में, गांधी परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा और सुझाव दिया कि मामले की सुनवाई 9 मार्च को की जाए। न्यायालय ने इस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी।

प्रतिवादी के रूप में नामित फर्मों में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद दुबे ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा और बताया कि उनके मुवक्किल को अपील बहुत देर से मिली थी। प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय को सूचित किया कि उसने तामील का हलफनामा पहले ही दाखिल कर दिया है। पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। नेशनल हेराल्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले राउज़ एवेन्यू न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए ईडी ने अपील दायर की है।

प्रतिवादियों में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ-साथ अन्य लोग भी शामिल हैं।

भारत पर फिर टैरिफ ठोकने वाले हैं ट्रंप? अमेरिकी सांसद के दावे से मचा हड़कंप!

वांशिगटन। क्या अमेरिका भारत पर फिर टेरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका में विपक्ष की पार्टी डेमोक्रेटिक के सांसद ब्रांड शेयरमैन इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भारत पर टेरिफ लगाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। ट्रंप दावा करते हैं कि भारत पर टेरिफ इसलिए लगाया गया क्योंकि वह रूस से तेल खरीदता है। जबकि हंगरी अपनी जरूरत का 90इ कच्चा तेल रूस से इंपोर्ट करता है। फिर भी उस पर तो कोई टेरिफ नहीं लगाया गया। चीन रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है लेकिन उस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। चीन पर जो सेंशंस लगे भी हैं उसकी वजह अलग है।

भारत अपनी जरूरत का केवल 21इ तेल रूस से लेता है। फिर भी हमारे मित्र देश भारत को निशाना बनाया जा

रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप को यह नीति तुरंत बदलनी चाहिए। यहां पर आपको यह क्लियर कर दें कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना पर टेरिफ लगा रहे थे तो इसके पीछे की उन्होंने सबसे बड़ी वजह यह बताई थी कि चाइना से फेंटिनल अमेरिका आ रहा था। इसलिए चाइना पर टेरिफ लग रहा है। लेकिन उन्होंने रशिया से तेल खरीदने की बात को नहीं बढ़ावा दिया था। इंडिया के लिए उन्होंने यह कहा था। आप समझते हैं कि भारत को इससे क्या नुकसान हो रहा है। जिओपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्मचलानी का कहना है कि इससे चीन की जीत हुई है। भारत अपनी जेब ढीली कर रहा है ताकि चीन को फायदा हो सके। उन्होंने आगे लिखा ट्रंप को लगता है कि वह ऐसा करके अपनी बात मनवा लेंगे क्योंकि उनके पिछले कार्यकाल के दौरान यह पैतरा काम कर गया था। तब उन्होंने भारत पर ईरान से तेल नहीं खरीदने का दबाव बनाया था।

भारत ने उनकी बात मान भी ली और ईरान से तेल लेना बंद कर दिया जो कि ईरान से सस्ता तेल हम लोगों को मिल रहा था। इसके बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर भारत अमेरिका पर निर्भर हो गया। फिर रूस की एंट्री हुई। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत को रूस से सस्ता तेल मिलने लगा तो भारत रूस की तरफ शिफ्ट हो गया। अब फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। भारत अब दोबारा अमेरिका से तेल पेट्रोलियम खरीदने लगा है। जबकि रूस से उसे सस्ता तेल मिल रहा है। वो आगे बताते हैं कि इसका नतीजा यह हुआ कि ईरान का सारा सस्ता तेल चीन खरीदने लगा और भारत को अमेरिका से महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने स्वीकार भी किया है कि भारत अब अमेरिका से तेल की खरीदारी बढ़ा रहा है। इसे इंपोर्ट डायवर्सिफिकेशन का नाम दिया जा रहा है।

इन 2 देशों से होगी भारत की अगली बड़ी जंग! इजराइल ने क्या खुलासा कर दिया?

ईरान पर अमेरिका के संभावित हमले से पहले इजराइल से एक होश उड़ा देने वाला बयान आया है। इजराइल ने दो देशों को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया है। लेकिन खतरनाक संयोग देखिए कि इन्हीं दोनों देशों ने अचानक भारत को चुनौती दे दी है। भारत से जंग की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें से एक देश तो बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही ढाका में रंगे हाथों पकड़ा गया है। आपको बता दें कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने बकायदा इन दोनों देशों का नाम लिया है और कहा है कि ये दोनों देश इजराइल के खिलाफ कट्टरता बढ़ा रहे हैं।

सऊदी अरब को भी हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। नेफ्ताली बेनेट ने कहा है कि यह दो देश हैं तुर्की और पाकिस्तान। नेफ्ताली ने कहा कि तुर्की दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। उन्होंने तुर्की को नया ईरान तक घोषित कर दिया है। नेफ्ताली बेनेट ने कहा है कि तुर्की सऊदी अरब को हमारे खिलाफ करने और न्यूक्लियर पाकिस्तान के साथ एक इस्लामिक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। आप यह मानकर चलिए कि अगर भारत का दूसरा युद्ध होता है तो वह इन दोनों ही देशों के साथ होगा। इजराइल ने जिस तुर्की को नया ईरान कहा है, वही तुर्की बांग्लादेश में तारिक रहमान के शपथ लेते ही पहुंच गया है। हैरानी की बात देखिए कि बांग्लादेश पहुंचते ही तुर्की के इस शख्स को देख पाकिस्तान में भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यहां तक बोल दिया है कि भारत से जंग होने वाली है।

शख्स जो चुपचाप तुर्की से बांग्लादेश पहुंचा है। इस व्यक्ति का नाम बिलाल एदवान है। बिलाल अर्दवान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एदवान का बेटा है। बिलाल अर्दवान लगातार जमात इस्लामी के संपर्क में भी रहा है। आपको बता दें कि तुर्की भारत के खिलाफ दो तरफ से फ्रंट खोलना चाहता है। पाकिस्तान की तरफ से पहला फ्रंट खोला जा चुका है अब बांग्लादेश से नया फ्रंट खोलने की तैयारी है। इसीलिए बिलाल अर्दवान बांग्लादेश पहुंचा है। बिलाल अर्दवान को बांग्लादेश में देख पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोल रहा है कि भारत से युद्ध की संभावना बढ़ गई है। ख्वाजा आसिफ आरोप लगा रहा है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान को मार रहे हैं।

यूनाइट्स स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज...पाकिस्तान ने अपनी इंग्लिश के जरिए पूरी दुनिया में करा ली बेइज्जती

पाकिस्तान एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय उपहास का पात्र बन गया है, जब उसके विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें कई स्पष्ट त्रुटियां थीं। बयान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और 18 से 20 फरवरी तक शांति बोर्ड के उद्घाटन सत्र में भाग लेने के लिए उनकी संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा का जिक्र था। व्यापक उपहास का कारण शीर्षक था, प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा। बयान में दो स्पष्ट वर्तनी त्रुटियां थीं, जहां 'यूनाइटेड' की जगह 'यूनाइट्स' और 'अमेरिका' की जगह 'अमेरिकास' लिखा गया था। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने तुरंत इन त्रुटियों को पहचान लिया और बार-बार होने वाली आधिकारिक गलतियों के लिए पाकिस्तान का मजाक उड़ाया।

सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रिया

पाकिस्तान (सिविलियंस) नाम के एक एक्स अकाउंट ने लिखा, लानत है तुम पर। एक अन्य यूज़र ने टिप्पणी की, 'थोड़ा ज्यादा पर्दा उठ गया भाई। एकजुट हो जाओ।' इन प्रतिक्रियाओं ने पाकिस्तान की बार-बार होने वाली ऑनलाइन गलतियों पर बढ़ती निराशा और मनोरंजन को उजागर किया।

पाकिस्तान की पहली चूक नहीं

यह पहली बार नहीं है जब ऐसी घटना घटी है। पिछले साल, जब इज़राइल ने ईरान पर हवाई हमले किए थे, तब एक वायरल स्क्रीनशॉट में दावा किया गया था कि शहबाज़ शरीफ़ ने गलती से 'मैं निंदा करता हूँ' की जगह 'मैं हमले का समर्थन करता हूँ' लिख दिया था। यह चूक तुरंत चर्चा का विषय बन गई और सभी मंचों पर पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का कारण बनी।

'Freebies' पर Supreme Court का बड़ा सवाल, घाटे में राज्य, फिर क्यों बांट रहे मुफ्त की रेवड़ियां?

नई दिल्ली। गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों के राजनीतिक दलों द्वारा 'मुफ्त योजनाओं' के वितरण की कड़ी आलोचना की और सार्वजनिक वित्त पर इसके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक दलों को मुफ्त योजनाओं के माध्यम से संसाधन वितरित करने के बजाय, ऐसी सुनियोजित नीतियां बनानी चाहिए जो लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाली योजनाएं पेश करें, जैसे कि बेरोजगारी योजनाएं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इस तरह के फिजूलखर्ची से देश का आर्थिक विकास बाधित होगा। हां, संसाधन उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है, लेकिन जो लोग मुफ्त योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं... क्या इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि राज्य घाटे में चल रहे हैं, फिर भी मुफ्त योजनाएं दे रहे हैं। देखिए, आप एक वर्ष में जो राजस्व एकत्र करते हैं, उसका 25 प्रतिशत राज्य के विकास के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता?

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के सभी राज्यों से संबंधित है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा कि हम किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी राज्यों की बात कर रहे हैं। यह नियोजित व्यय है। आप बजट प्रस्ताव क्यों नहीं पेश करते और यह औचित्य क्यों नहीं देते कि यह बेरोजगारी पर मेरा व्यय है? कभी मात्र चुनावी वादे माने जाने वाले मुफ्त पैकेज अब भारत में चुनाव जीतने की एक महत्वपूर्ण रणनीति बन गए हैं।

अचानक 70 देशों के जंगी जहाज आ पहुंचे भारत, क्या है बड़ा प्लान?

नई दिल्ली। एक तरफ अमेरिका ने ईरान का घेराव कर लिया है। युद्धपोत को समंदर में उतार दिए हैं। कई यहां पर सैन्य गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में अचानक 70 देशों के जंगी जहाज आ पहुंचे हैं। जिसने पूरी दुनिया में इस वक्त खतरनाक तहलका मचा दिया है। यह 70 जंगी जहाज अमेरिका, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया और तमाम देशों से विशाखापट्टनम पहुंच चुके हैं। बता दें कि इस बार 4 मार्च को होली है। कहते हैं होली में दुश्मन भी गले मिल जाते हैं और भारत में होली से पहले ऐसा ही एक मिलन होने जा रहा है। दुनिया के दो परंपरागत प्रतिविधि अमेरिका और रूस दोनों की नौसेनाएं भारत के विशाखापट्टनम के समंदर में मौजूद है। यानी भारत एक ऐसा मंच बन चुका है जहां वैश्विक ताकतें आपसी मतभेद के बावजूद एक साथ खड़ी हो सकती है और यह एक कूटनीति का एक जरिया भी है जिस पर भारत पर जो दूसरे देश हैं वह भरोसा करते हैं कि अगर कूटनीति करनी है तो भारत जाना होगा।

बता दें कि तीन बड़े इवेंट हो रहे हैं। एक बड़ा संदेश यहां जमावड़ा सिर्फ अभ्यास नहीं है। यह तीन बड़े नौसैनिक आयोजनों का संगम है। पहला इंटरनेशनल फ्लट रिव्यू यानी कि आईएफआर 2026 इसके बाद एक्सरसाइज मिलन 2026 और इसके बाद आईओएस कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स। 15 फरवरी से 24 फरवरी तक चलने वाले इस मेगा इवेंट में 72 कंट्रीज के 60 से ज्यादा युद्धपोत हिस्सा लेने के लिए आ पहुंचे हैं। मिलन 2026 का औपचारिक उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापटनम में किया। वहीं बता दें कि यह आयोजन भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय विशाखापटनम में हो रहा है और इसकी कई सारी तस्वीरें और वीडियोस इस वक्त जमकर सोशल मीडिया पर वायरल है। इस इंटरनेशनल फ्लट रिव्यू में भारत ने अपना 76इ स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत भी उतार दिया है। जिसके वीडियो सामने आते ही खतरनाक भूचाल भी आ गया है।

इसके साथ ही स्वदेशी फ्रिगेट, विध्वंसक पोत, स्टील जहाज, पनडुपी रोधी कॉरवेट और सबमरीन भी प्रदर्शन यहां पर जमकर कर रहे हैं। यह सिर्फ ताकत दिखाना नहीं। यह संदेश है कि भारतीय नौसेना का बजट अब घरेलू निर्माण और समुद्री आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हिंद महासागर और यह मिलन एक्सरसाइज? बता दें कि भारत का 11,000 से भी ज़्यादा का किलोमीटर लंबा जो तटीय इलाका है, उसमें 1300 से ज़्यादा द्वीप है।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 **Twitter:** https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 **Mobile No:** 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी

E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)